वर्ष : 17 ❖ अंक : 348 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक

गुरुवार, 27 जुलाई 2023

यूसीसी पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा : सिद्धारमैया 3 | मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया गया, मेरा अपमान हुआ है : खड़गे 8

एसकेएम सरकार राजनीतिक लाभ के लिए समाज को विभाजित नहीं करती है : सीएम

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 26 जुलाई । सिक्किम पूर्व विधायक परिसंघ द्वारा आज अपना 21वां स्थापना दिवस लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय मनन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पसांग दोरजी सोना विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गौरतलब है कि 2002 में स्थापित सिक्किम पूर्व विधायक परिसंघ राज्य में पूर्व विधानसभा सदस्यों का एकमात्र संगठन है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री गोले ने पूर्व विधायकों को लेकर कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन पर शीघ्र ही परिसंघ का कार्यालय और गेस्ट हाउस बनाया जायेगा। वहीं, उन्होंने पूर्व विधायकों की पेंशन राशि में वृद्धि हेतु जल्द ही अधिसूचना जारी करने और साल में एक बार पूर्व विधायकों को दौरे पर भेजने की भी घोषणा भी की॥ इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगले वर्ष से राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के तत्वावधान में सिक्किम पूर्व विधायक परिसंघ का स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा।

वहीं, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गोले ने परिसंघ की स्थापना दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों एवं पूर्व विधायकों को बधाई दी और सिक्किम पूर्व विधायक परिसंघ को एक गैर-राजनीतिक संस्था बताते हुए इसे राजनीतिक चश्मे से न देखने का आग्रह किया। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए समाज को विभाजित नहीं करती है और सामाजिक संगठन में राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने जाति को बांटने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिक्किम के निर्माण के लिए काम किया है।

वहीं, परिवर्तन के नारे के साथ आई एसकेएम सरकार पर विफलता संबंधी विपक्ष के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री गोले ने कहा कि आज राज्य में ऐसे कई बदलाव हुए हैं, जिन्हें पांच सितारा होटलों में ठहरने वालों द्वारा देखा और महसूस नहीं किया जा सकता है। इस दौरान राज्य के विकास में पूर्व विधायकों के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार तथा राज्य की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार पूर्व विधायकों और उनके संगठन के सहयोग हेतु हमेशा तैयार है।

कार्यक्रम में 21वें स्थापना दिवस पर पूर्व विधायक परिसंघ ने पूर्व लोकसभा सांसद नकुल दास राई और राज्यसभा सांसद पीटी ग्यामछो सहित तीसरी और चौथी राज्य विधानसभा के 20 पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया। वहीं, पूर्व विधायकों के हित में राज्य सरकार द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्यों के लिए परिसंघ की ओर से मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले को बधाई दी गई। इस अवसर पर अंतर विद्यालय एवं अंतर महाविद्यालय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार दिया गया।

कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने भी संबोधित किया।

विकास में चालकों की भूमिका महत्वपूर्ण : खालिंग

राज्यस्तरीय सारथी सम्मान दिवस आयोजन की तैयारी पूरी

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 26 जुलाई । कल गुरुवार को सरमसा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सारथी सम्मान दिवस की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंत्री, चालकों समेत तमाम एसकेएम नेता जुटे हुए हैं।

इसी बीच, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग ने आज सुबह आयोजन की कार्य प्रगति का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सारथियों के सम्मान वाले इस कार्यक्रम की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र के विकास में चालकों और सारथियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने बिना चालकों-वाहकों के किसी के भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकने का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी सुविधा का मुख्य आधार चालक-वाहक ही होते हैं। उन्होंने कहा कि धूप, बारिश, भूख, सुबह और रात जैसी परिस्थितियों में भी यदि ड्राइवर वाहन नहीं चलाएंगे तो हमारा जीवन रूक जाएगा। हमारे जीवन को सक्रिय रखने वाले ड्राइवरों के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 2019 में एसकेएम पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पीएस गोले की दूरदर्शी सोच के अनुरूप सारथी सम्मान दिवस के माध्यम से राज्य के चालकों और सारथियों को सम्मानित किये जाने की परंपरा शुरू की गई है।

उल्लेखनीय है कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य भर के ड्राइवरों को सारथी उपनाम से सम्मानित करती है। इनके सम्मान में हर साल 27 जुलाई को सारथी सम्मान दिवस मनाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सारथियों को सम्मानित किया जाता है और सारथियों को वाहन भी प्रदान किया जाता है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 26 जुलाई । सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की अध्यक्षता में आज राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर तेलांग एवं विभाग के अधीनस्थ समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं एससीइआरटी के उच्च पदाधिकारियों के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में परस्पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से इसे शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक सभी को एक साथ लेकर जमीनी स्तर पर मिशन मोड पर कार्य करने की अवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य आत्महीनता से उठकर आत्मबल, आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख होना है। इस बैठक में राज्यपाल ने विशेष कर सभी बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल करने और सभी मानक विद्यालयों को एनसीसी से जोड़ने पर जोर दिया।

इस दौरान नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य में क्रियान्वित योजनाओं एवं पहल को समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं एससीइआरटी के निदेशकों द्वारा विस्तार से पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसी सन्दर्भ में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आर तेलंग ने शिक्षा के क्षेत्र में सिक्किम द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डाला। कड़ी को जोड़ते हुए ,एससीइआरटी के निदेशक डॉ रॉबिन छेत्री ने 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' (ईसीसीई) एवं 'मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता' के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया।

इस दौरान उच्च शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक, उज्जवल राई ने कई बिंदुओं पर सभा का ध्यान आकर्षित किया। इस बैठक में निदेशक, उच्च शिक्षा श्रीमती होंडाला ग्यालसेन, संयुक्त निदेशक एससीईआरटी, छिरिंग भूटिया आदि उपस्थित रहे।

सीएपी की लोकप्रियता से डरी सरकार : हेमराज अधिकारी

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 26 जुलाई । सिटीजन एक्शन पार्टी (सीएपी) ने पार्टी के मुख्य समन्वयक गणेश राई पर दर्ज मामलों की निंदा करते हुए कहा है कि पार्टी की लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है इसलिए श्री राई के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इस आशय की बात यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी के प्रवक्ता हेमराज अधिकारी ने कही।

उन्होंने कहा कि सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम की गति को कम करने के लिए पार्टी के मुख्य समन्वयक श्री गणेश राई के खिलाफ साजिशन झूठे मामले दर्ज किए गए। यह सरकार की कायरता के अलावा कुछ नहीं है। सिटिजन एक्शन पार्टी-सिक्किम सिक्किम को एक समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में सिक्किम के सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य मुद्दों पर सुधार को लेकर राजनीति कर रही है। स्वाभाविक है कि पार्टी का उक्त कार्यक्रम सिक्किम के श्रमिकों, किसानों, युवाओं, छात्रों, विद्वानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को आकर्षित करता है।

उन्होंने कहा कि सिक्किम के नागरिकों का जबरदस्त जनसमर्थन देखने के बाद यह साफ है कि मौजूदा सरकार में उथल-पुथल मची हुई है। इसी के चलते सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम के नेता श्री गणेश राई के खिलाफ झूठे मुकदमे और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम इसकी कड़ी निंदा करती है।

अधिकारी ने कहा कि लोगों की आवाज दबा कर सत्ता द्वारा मुर्दा शांति स्थापित करने की राजनीतिक संस्कृति पुरानी है। एक के बाद एक सरकार इसका अनुसरण करती आ रही है। जब-जब जनता सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होती है, तब-तब सरकार नए-नए परिदृश्य एवं षडयंत्र रचती है तथा जनता के पक्ष में बोलने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जन आन्दोलन को कमजोर करने का असफल प्रयास करती है। लेकिन सत्ता जनआंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती है, बल्कि निरंकुश सत्ता का जनविरोधी चरित्र और अधिक खुल जाता है। इससे जन आन्दोलन और अधिक सशक्त हो जाता है।

उन्होंने कहा कि सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम का राज्य में तेजी से विस्तार हो रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार तरह-तरह की अफवाहें और निराधार खबरें फैला रही है तथा लोगों के बीच स्थापित विश्वास और सीएपी-सिक्किम की लोकप्रियता को कमजोर करने का असफल प्रयास कर रही है जो वास्तव में घृणित है। उन्होंने कहा कि सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम एक व्यक्ति द्वारा संचालित निजी संगठन नहीं है, यह सिक्किम के लोगों की भावना से पैदा हुई पार्टी है, जो व्यापक समर्थन और संरक्षण के साथ आगे बढ़ रही है। सभी सिक्किमी नागरिकों की, वर्तमान शिक्षित युवा पीढ़ी की नियति और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ही इसका गठन किया गया है। सिटीजन एक्शन पार्टी-सिक्किम की बढ़ती लोकप्रियता वर्तमान समय की मांग है और यह सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है।

राज्य चलाने में महिलाओं की भूमिका अनिवार्य : एमएन दहाल

अनुगामिनी नि.सं.

यांगयांग, 26 जुलाई । मुख्य विपक्षी एसडीएफ पार्टी चेली मोर्चा ने सोमवार को दक्षिण सिक्किम के यांगयांग में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। महिला समूहों को राज्य की वर्तमान राजनीति और उनकी भूमिका के बारे में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया था।

शिविर में केजे भूटिया की विशेष उपस्थिति में दक्षिण जिला प्रचार सचिव दिलू दहाल, दक्षिण जिला छात्रा महासचिव अनिता गौतम, लाकी भूटिया, विनीता राई प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। मणिपुर की घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर शुरू किये गये कार्यक्रम में एसडीएफ पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमएन दहाल मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएन दहाल ने कहा कि एसडीएफ पार्टी विचारों की जमीन पर आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह घर चलाने के लिए महिला की जरूरत होती है, उसी तरह राज्य चलाने में भी महिलाओं की भूमिका अनिवार्य है। दहाल ने सिक्किम में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में आने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की मिट्टी और अस्तित्व को बचाने के लिए राज्य के गांवों में महिलाओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है।

निर्मला गुरुंग के संचालन में हुए कार्यक्रम को प्रचार सचिव दिलू दहाल ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में दहाल ने महिलाओं से राज्य के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को साफ करने का साहस दिखाने का आह्वान किया। इसी तरह दक्षिण जिला महासचिव अनिता गौतम ने कहा कि सिक्किम के स्वाभिमान और मिट्टी को बचाने के लिए सिक्किम की महिलाओं को संगठित होना होगा।

सिक्किम सुधार अभियान में सत्तारूढ़ पार्टी डाल रही है अड़चन : एलपी काफ्ले

सीएपी ने सीएम पद के उम्मीदवार के चयन के लिए गठन की समिति

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 26 जुलाई । अपनी स्थापना के छह महीने पूरे करने के साथ ही सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम ने राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लक्ष्य के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत आज पार्टी ने आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन हेतु 12 सदस्यीय चयन समिति का गठन भी कर दिया है। सीएपीएस अध्यक्ष एलपी काफ्ले ने आज यहां इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पार्टी के छह महीने पूरे करने पर पर राज्यवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं।

आज यहां एक पत्रकार सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष एलपी काफ्ले ने पार्टी स्थापना के बाद आधे वर्ष पूरे करने के अनुभव एवं इस दौरान अपने सिक्किम सुधार अभियान में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा डाली जा रही अड़चनों के बारे बताया। उन्होंने पार्टी द्वारा 6 महीने में हासिल की गई कई उपलब्धियों और मौजूदा एसकेएम सरकार द्वारा पार्टी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि हमने पार्टी की घोषणा के लिए जो जगह चुनी, उसे कई बहानों से अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में हमने मल्ली सड़क स्थित टाटा स्टैंड पर पार्टी की घोषणा की। उसके बाद भी पार्टी सिक्किम और यहां के लोगों की चिंताओं के तमाम मुद्दों को उठाती रही है। इसके तहत 200 से अधिक पार्टी सदस्यों की एक टीम ने गंगटोक जिला कार्यालय परिसर में धरने के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी धरना दिया।

पार्टी अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी पार्टी ने सिक्किम की सभी मांगों और विशेषकर नेपालियों पर लगे विदेशी होने के कलंक, सिक्किमी परिभाषा में बदलाव, संविधान के अनुच्छेद 371एफ के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया है। वहीं, हमारी टीम ने विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन लेकर देश के विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की और उन्हें सिक्किम और यहां के लोगों की सभी मौजूदा समस्याओं से अवगत कराया। इसके अलावा, इन समस्याओं और मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। वहीं, पार्टी के विकास और

विस्तार कार्यों के बारे में उन्होंने केंद्रीय कार्यकारी परिषद, जिला कार्यकारी परिषद और क्षेत्रीय कार्यकारी परिषद का गठन कर ग्रामीण स्तर तक पहुंचने में सफल रहने का दावा किया।

सीएपीएस अध्यक्ष ने आगे कहा कि थोड़े समय में ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपार जनसमर्थन प्राप्त कर पार्टी आगामी चुनाव में जीत का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम

■ शेष पृष्ठ ०३ पर

डियर साप्ताहिक लॉटरी नदिया निवासी ने ₹ 1 करोड़ जीते

नदिया, पश्चिम बंगाल के श्री गोबिन्द सरकार ने **02.06.2023** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **73H 89671** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। ''डियर लॉटरी का नाम जीवन भर हमेशा मेरे हृदय में बना रहेगा, क्योंकि इसने मुझे एक करोड़पति बना दिया है। मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए एक करोड़पति बनने का यहां दूसरा कोई जरिया या रास्ता नहीं है। महज कुछ रुपए खर्च कर ही हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में डियर लॉटरी द्वारा बनाए गए करोड़पतियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।'' विजेता ने कहा।

काले कपड़ों में संसद आएंगे विपक्षी सांसद, कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। संसद में गुरुवार को विपक्ष के सभी सांसद काले कपड़ों में नजर आएंगे। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए यह निर्णय लिया है। यह फैसला गुरुवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक में लिया गया।

इसी बीच बुधवार शाम राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद व मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने पार्टी के सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइनों का व्हिप जारी किया है। व्हिप में कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों से कहा गया है कि गुरुवार 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा में बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है पूर्वाह्न 11 बजे से सदन में उपस्थित रहें।

कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को 27 और 28 जुलाई को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। बुधवार शाम पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी करते हुए कहा कि स्थगन तक गुरुवार, 27 जुलाई को सदन में रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।

दरअसल, केंद्र सरकार दिल्ली से संबंधित अपने अध्यादेश के स्थान पर राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक लाने की तैयारी में है। यह विधेयक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक प्राधिकार गठित करने का प्रावधान करता है। सरकार राज्यसभा में यह विधेयक लाएगी। सरकार की इस तैयारी के बीच कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर गुरुवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पेश करेगी। हालांकि, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसका विरोध करते हुए 'आप' के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है।

दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार का मामला सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में था। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं। सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक इस आदेश के कुछ दिन बाद केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश ने दिल्ली सरकार से नियंत्रण लेकर इसे एलजी को सौंप दिया। इस अध्यादेश को अब विधेयक के रूप में लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी दिलाई जानी है।

'2004-09 तक नहीं मनाया करगिल विजय का जश्न', राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 2004-09 के दौरान 'करगिल विजय दिवस' नहीं मनाया था, लेकिन अब वे अपने गठबंधन के एक नए नाम के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने 2009 में राज्यसभा में अपने प्रस्ताव की प्रतियां साझा करते हुए एक ट्वीट में कहा, 'क्या आप जानते हैं कि 2004-2009 के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया या सम्मान नहीं किया, जब तक कि मैंने संसद में जोर नहीं दिया।'

उन्होंने प्रस्ताव में लिखा था कि जो सदस्य इस आधार पर जश्न का विरोध करते हैं कि यह 'भाजपा का युद्ध' है, उन्हें यह मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, 'यह हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इन बलिदानों और कर्तव्यों को याद करें। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी।' भाजपा नेता ने कहा, 'मेरी लगातार मांग के बाद ही तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 2010 से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने की परंपरा शुरू की थी।'

उन्होंने कहा, 'यह वही यूपीए है जो अपनी शर्म छोड़कर एक नए नाम के पीछे छिपना चाहती है। एक राजनीतिक दल और राजवंश जो कारगिल विजय दिवस या हमारे सशस्त्र बलों की सेवा और बलिदान और पाकिस्तान पर जीत का जश्न नहीं मनाना चाहता था, अब खुद को 'भारत' के रूप में फिर से ब्रांड करना चाहता है। यही कांग्रेस है, जिन्होंने बालाकोट हवाई हमलों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाया, वे विदेशों में हर अवसर पर भारत को बदनाम करते हैं और फिर भी खुद को 'इंडिया' के रूप में पेश करना चाहते हैं।'

करगिल विजय दिवस पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। चंद्रशेखर लंबे समय से सुरक्षा बलों के समर्थक मुद्दों से जुड़े रहे हैं और दिल्ली तथा बेंगलुरु में युद्ध स्मारकों के प्रबल समर्थक रहे हैं।

ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर वर्तमान ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के अनुसार उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। अदालत गुरुवार (27 जुलाई) को केंद्र के आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमत हुई।

एसजी मेहता ने अदालत से शुक्रवार से पहले केंद्र के विविध आवेदन पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार अपराह्न 3:30 बजे तय की।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए गए, एक फैसले में 2021 में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करने के लिए ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को 'अवैध' करार दिया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।

अदालत ने माना था कि मिश्रा को दिया गया विस्तार इसे संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 2021 के पहले दिए गए फैसले के विपरीत था।

मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया। मई 2020 में वह 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे।

हालाँकि, 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश को इस आशय से संशोधित किया था कि 'दो साल' की अवधि को 'तीन साल' की अवधि में बदल दिया गया था। इसे एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 के फैसले में संशोधन को मंजूरी दे दी, लेकिन मिश्रा को और विस्तार देने के खिलाफ फैसला सुनाया।

वर्ष 2021 में अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश लेकर आई, जिससे उसे ईडी निदेशक के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई। इस संबंध में संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया था, जिसमें ईडी निदेशक के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, जो अधिकतम पांच साल तक हो सकता है।

कोर्ट ने 11 जुलाई को आदेश दिया, 'सीवीसी अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को इस हद तक खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय कुमार मिश्रा को दिया गया विस्तार अवैध है। हालांकि, उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति है।'

'एनडीए में सिर्फ तीन ही मजबूत दल- ईडी, सीबीआई और आईटी', उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज

मुंबई, 26 जुलाई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केवल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तीन मजबूत दल हैं।

ठाकरे ने राज्यसभा सदस्य एवं शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए इंटरव्यू के दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर-पूर्वी राज्य का दौरा करने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की हालिया बैठक पर निशाना साधते हुए, ठाकरे ने कहा कि जब चुनाव करीब आते हैं तो भाजपा को अपने सहयोगियों की याद आती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो यह मोदी सरकार बन जाती है।

गौरतलब है, एनडीए में शामिल 38 दलों के नेताओं की पिछले हफ्ते दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उसी दिन शिवसेना (यूबीटी) समेत विपक्ष के 26 दलों ने बेंगलुरु में बैठक की थी। इस दौरान विपक्ष दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) रखा था। विपक्षी दल पहले भी सत्तारूढ़ भाजपा पर विरोधियों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि एनडीए में 36 दल हैं। हालांकि, केवल ईडी, सीबीआई और आयकर एनडीए की तीन मजबूत पार्टी हैं। अन्य दल कहां हैं? कुछ दलों का तो एक भी सांसद नहीं है।

बता दें, इंटरव्यू का पहला हिस्सा बुधवार को सामना में प्रकाशित किया गया है। इस दौरान ठाकरे ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून लाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कानून के सामने हर कोई समान है, तो भाजपा में जो लोग भ्रष्ट हैं, उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए।

शिवसेना को लेकर उन्होंने कहा कि असली शिवसेना वहीं है, जहां ठाकरे परिवार है। जिन लोगों ने शिवसेना में फूट डाली थी, उन्होंने सोचा था कि इससे पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन यह फिर से उभर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि बगावत करने वाले कई दिग्गज लंबे समय से अपनी सीटों पर काबिज हैं। अब उनकी जगह नए लोगों को मौका मिल सकता है।

विधायक एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने पिछले साल जून में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे पार्टी में फूट पड़ गई थी और ठाकरे नीत महा विकास आघाडी की सरकार गिर गई थी। शिंदे बाद में भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए।

मुख्यमंत्री शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं के बारे में ठाकरे ने कहा कि अगर राज्य विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर न्याय नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी के लिए उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं।

यूपी में आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद, कार्रवाई करे सरकार : मायावती

लखनऊ, 26 जुलाई (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यूपी में आपराधिक तत्वों के हौसले काफी बुलंद हैं।

इस मामले में सरकार कार्रवाई करे। बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि यूपी में आपराधिक तत्वों के हौसले कितने बुलन्द हैं इसका एक और नमूना आज गोरखपुर के चिल्लूपार क्षेत्र के रुदौली में देखने को मिला। जब अवैध खनन करने वाले गिरोह ने दलित परिवार पर हमला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी व अन्य कई लोगों को घायल कर दिया। यह अति-दुःखद व अति-निन्दनीय।

बसपा मुखिया ने लिखा कि यूपी सरकार घटना का तुरन्त संज्ञान लेकर सभी नामजद लोगों के खिलाफ तत्काल उचित धाराओं में सख्त एक्शन लेने के साथ ही अपराध नियंत्रण व इस प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक अपराधों/उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लग सके, बीएसपी की यह मांग।

बता दें कि गोरखपुर जिले में बड़हलगंज थाना क्षेत्र के रुदौली, मझवलियां गांव के पास राप्ती नदी के किनारे से मंगलवार की रात से ट्रैक्टर ट्राली से खनन हो रहा था। इस बीच ट्रैक्टर चालक अश्लील गाना बजा रहे थे। जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इस बात को लेकर बुधवार की सुबह बगल के गांव दवनाडीह के कुछ लोग बोलेरो गाड़ी से बड़ी संख्या में असलहा लेकर पहुंच गए। उन्होंने रुदौली गांव में घुसकर गाली-गलौज की। इसी बीच गांव के राजकिशोर रामकेवल ने इसका विरोध किया। नाराज बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। इस बीच एक व्यक्ति ने असलहा निकालकर फायर कर दिया, जिससे राजकिशोर के सीने में गोली लग गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गांव के अरविंद, सूर्यप्रकाश व सुभाष घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बड़हलगंज लाकर इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुदौली में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। मृतक राजकिशोर चार बच्चों का पिता था। वह मनरेगा में मजदूर था।

लोकसभा में भारी हंगामा, अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर लगातार पांचवे दिन बुधवार को भी लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा।

बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने कारगिल की लड़ाई के शहीदों को नमन करते हुए कुछ देर मौन रहकर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही को शुरू किया, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई ने खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का जिक्र किया।

इस पर स्पीकर ने चौधरी को कहा, आप अनुभवी सांसद हैं और नियम प्रक्रिया की जानकारी आपको है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और बीआरएस सांसद नमा नागेश्वर राव ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष ने भले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है लेकिन भारत की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता पहले भी इन्हें सबक सीखा चुकी है।

इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं।

इस बीच कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित कई दलों के सांसद मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान वाले बैनर लहराते हुए वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

सत्ता पक्ष की तरफ से राजस्थान के भाजपा सांसदों ने अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर सदन में लाल डायरी लहराते हुए अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

इससे पहले राजस्थान भाजपा सांसदों ने प्रभारी अरुण सिंह के साथ संसद भवन परिसर के गेट नंबर 4 पर भी लाल डायरी लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

इस बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने भी अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी और हंगामे के बीच बिरला ने सदन चलाने का प्रयास किया लेकिन नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

'देश देख रहा आपकी कथनी-करनी का अंतर'

संसद में गतिरोध को लेकर खड़गे की शाह को चिट्ठी, बोले- हम हर कीमत चुकाएंगे

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री से संसद में आने और बोलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। हम इस देश के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसके लिए हर कीमत चुकाएंगे...लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के आचरण के रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं।

पत्र में आगे कहा गया है कि आपको ध्यान होगा कि मणिपुर में तीन मई के बाद की स्थिति पर 'इंडिया' के घटक दलों की लगातार मांग रही है कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर पहले अपना बयान दें, जिसके बाद दोनों सदनों में इस विषय पर विस्तृत बहस और चर्चा की जाए। जिस तरह की गंभीर स्थिति पिछले 84 दिनों से मणिपुर में व्याप्त है और जिस तरह की घटनाएं एक-एक कर सामने आ रही हैं, हम सभी राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित है कि हम वहां पर तत्काल शांति बहाली के लिए एवं जनता को संदेश देने के लिए देश के सर्वोच्च सदन में कम से कम इतना तो करेंगे। हम सामूहिक रूप से यही मांग कर रहे हैं।

छोटी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाकर माननीय सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ऐसा तब, जबकि नियम इस विषय में यह है कि किसी सदस्य का निलंबन उसी घटना के लिए एक सत्र से अधिक जारी नही रह सकता।

रोज 267 नियम के तहत विपक्षी सांसदों द्वारा बहस की नोटिस दी जाती है परंतु सत्तापक्ष में बैठे लोग ही सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करते हैं। विपक्ष के नेता जब चेयरमैन की अनुमति के बाद बोलने के लिए खड़े होते हैं तो स्वयं सदन के नेता बिना निवेदन और चेयरमैन की अनुमति के बाधा डालते हैं। आसन एवं सदन की परंपरा की अवमानना करते हैं। ऐसा पूरे सदन के समक्ष और लगातार हो रहा है। विपक्षी दलों के सदस्य हर स्थगन के बाद सदन में इसी आशा के साथ एकत्रित होते हैं कि सदन की कार्यवाही शायद सुचारू रूप से चलाई जाएगी परंतु अबतक निराशा ही हाथ लगी है।

पत्र में कहा गया है, प्रधानमंत्री जी से हम सदन में आकर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं परंतु ऐसा लगता है कि उनका ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। हमारी इस देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए हर कीमत देंगे। सत्तापक्ष यदि सचमुच सदन की कार्यवाही चलाने की इच्छा रखता है तो यह आसानी से विपक्ष को बोलने का मौका देकर किया जा सकता है। इसके लिए आसन अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह सदन के नेता का व्यवहार पूर्व-निर्धारित-प्रतिक्रिया संचालित न होकर सामान्य एवं सकारात्मक हो सकता है। यह सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगा। सत्र के दौरान रोज सरकार और विपक्ष का आचरण सदन के सामने रहता है आज भी रहेगा। गृहमंत्री जी की कथनी और करनी में कितनी समानता रहेगी, यह पूरा विपक्ष समेत देश देखेगा।

आईआरटी के लिए कार्यशाला आयोजित

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 26 जुलाई । इंसीडेंट रेस्पांस टीमों एवं अन्य हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए एमएचआरवीए मानचित्र को डीडीएमपी में शामिल करने और इससे संबंधित चर्चा हेतु आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा डीसी सभागार में आईआरटी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का संचालन डीपीओ श्रीमती रजनी पेगा ने किया। उन्होंने बताया कि डीडीएमपी में एमएचआरवीए, रोकथाम, नियंत्रण, तैयारी के उपाय, प्रतिक्रिया योजना और प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने डीडीएमपी की प्रस्तुति दी और मौजूदा जिला प्रोफाइल पर भी प्रकाश डाला।

इस दौरान, डीडीएमए अध्यक्ष सह डीसी भीम ठटाल ने दिशानिर्देशों में उल्लेखित प्रत्येक हितधारक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए आपातकालीन उत्तरदाताओं को अपने संबंधित स्थान के आधार पर डीडीएमपी से परिचित होने की जरूरत बताई। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न प्रावधानों और सुविधाओं को सुव्यवस्थित और व्यवहार में लाने का सुझाव दिया। इनमें विशेष कर संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा आने पर प्रभावी संचार हेतु जिला आपातकालीन नोडल अधिकारियों को स्मार्टफोन की उपलब्धता, आपदा के दौरान चौबीसों घंटे संचार माध्यम से सहायता आदि शामिल रहे।

वहीं, डीसी ने बीडीओ को अपने संबंधित क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय और भौतिक मैपिंग करने की याद दिलाई। इसी तरह, उन्होंने सभी आईआरटी को चेयरपर्सन की मंजूरी हेतु डीडीएमपी को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक और सुझाव देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बैठक में एडीसी धीरज सुबेदी एवं एसडीएम सनी खेरल के अलावा बीडीओ, संबंधित विभागों के अधिकारी और सेकेंड आईआरबी बटालियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

यूसीसी पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा : सिद्धारमैया

बेंगलुरु, 26 जुलाई (एजेन्सी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र इस मुद्दे हो हवा दे रहा है और एक अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

सिद्धारमैया ने उनसे मुलाकात करने आए एआईएमपीएलबी के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन नहीं होने देगी। आगे कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

सीएम कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सीएम के गृह कार्यालय में एक चर्चा के दौरान, एआईएमपीएलबी सदस्यों ने यूसीसी के कार्यान्वयन के कारण मुसलमानों के अधिकारों और मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने

मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले विधि आयोग ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस विविधतापूर्ण देश में यूसीसी का कार्यान्वयन संभव नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के हवाले से कहा गया कि अब केंद्र सरकार ने वर्तमान विधि आयोग से इस मामले की दोबारा समीक्षा करने को कहा है। तदनुसार, विधि आयोग जनता से राय एकत्र कर रहा है। जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के मसौदे पर जवाब देंगे। हमारी सरकार कभी भी अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन नहीं होने देगी। केंद्र सरकार चुनाव के मद्देनजर अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है।

सोनिया गांधी ने संजय सिंह से की मुलाकात, कहा- हम आपके साथ

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की, जिन्हें संसद में 'अनियंत्रित व्यवहार' के लिए मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है।

सोनिया गांधी ने संजय सिंह से कहा कि 'आपको हमारा पूरा समर्थन है।'

पार्टी सूत्रों के अनुसार, सोनिया गांधी ने संसद पहुंचने के बाद सिंह से मुलाकात की जो पिछले दो दिनों से संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं।

सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने सिंह से कहा कि उन्हें उनका पूरा समर्थन है।

सिंह को सोमवार को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। वह सदन में अनियंत्रित हो गए थे और मणिपुर हिंसा पर लगातार विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे थे।

सोमवार से वह संसद परिसर में अपने निलंबन के विरोध में बैठे हुए हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस यानि इंडिया के कई सांसद सिंह के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं।

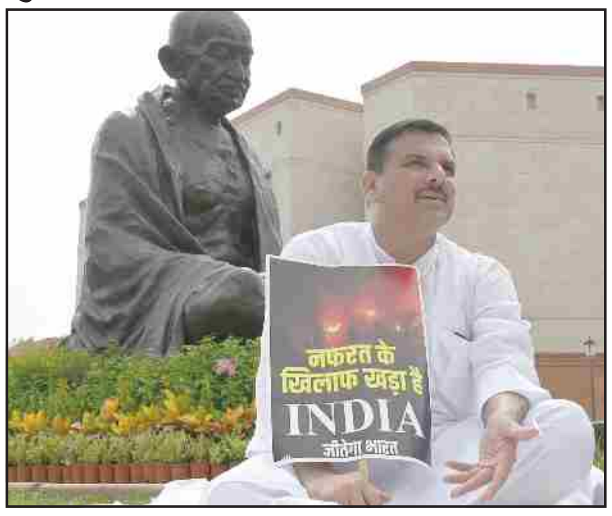

विपक्षी सांसद संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं और संसद में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की भी मांग कर रहे हैं।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पारित करने के लिए सांसद बिष्ट ने जताया आभार

अनुगामिनी नि.सं.

दार्जिलिंग, 26 जुलाई । दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने आज संसद में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर चर्चा करने और इसे पारित करने के लिए लोकसभा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे मौजूदा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को अपडेट करने वाला बताया है।

एक विज्ञप्ति के माध्यम से सांसद ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह विधेयक वन संसाधनों को भावी पीढियों के लिए बनाए रखने के साथ ही इसके वर्तमान उपयोग के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह विधेयक वन आधारित समुदायों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। उनके अनुसार, यह शायद पहली बार है कि वन समुदायों के अधिकारों को इतनी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ।ऐसे में यह विधेयक वन समुदायों को जंगलों का संरक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने आगे बताया कि यह विधेयक 2070 तक हमारी सरकार की शुद्ध शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को ठोस आधार प्रदान करते हुए देश के एक तिहाई हिस्से तक वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके अलावा, विधेयक में वनों की समग्र अखंडता सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार के पास हस्तक्षेप की अनुमति का अधिकार है जिससे यह विभिन्न राज्य सरकारों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार केंद्रीय मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। उनके अनुसार, इसका मतलब यह होगा कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन में देरी करना जारी रखती है, या यदि सिनकोना बागान भूमि को हटाना चाहती है, तो केंद्र सरकार लोगों के पक्ष में उसमें हस्तक्षेप कर सकती है।

सांसद बिष्ट ने यह भी बताया कि वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक रणनीतिक सीमा क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को विकसित करने का भी प्रावधान करता है। यह रेल लाइन या सार्वजनिक सड़कों के रखरखाव, रक्षा संबंधी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी परियोजनाओं के लिए भी जगह बनाता है। ऐसे में ये प्रावधान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में मदद के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेंगे।

सांसद ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने सदन को बताया कि कैसे विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था, जिसका मैं भी एक हिस्सा था। इसने हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से टिप्पणियां और इनपुट आमंत्रित किए थे जिनमें सीमावर्ती राज्यों, पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, विकास एजेंसियों, सरकारी निकायों से इनपुट विशेष रूप से आमंत्रित और शामिल किए गए थे। इसमें हमें विभिन्न राज्य सरकारों, विभागों और मंत्रालयों से टिप्पणियों के साथ कुल 1309 ज्ञापन प्राप्त हुए थे।

सिक्किम सुधार अभियान ....

है। ऐसे में उन्होंने वर्तमान समय को सिक्किम के सुधार का समय बताते हुए राज्य के हितों की रक्षा के लिए सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम को ही एकमात्र विकल्प बताया। उल्लेखनीय है कि आज सीएपीएस द्वारा आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए गठित चयन समिति में विष्णु चामलिंग को अध्यक्ष और डीबी चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं समिति के अन्य सदस्यों में लाकपा शेरपा, श्रीमती गीता कार्की, एमबी लिम्बू, डीबी गुरुंग, ओंगदिला भूटिया, भूषण अधिकारी, रबी गुरुंग, जेरबो लेख्चा, नरेंद्र अधिकारी और वित्र आचार्य शामिल हैं।

मणिपुर पर उद्धव ठाकरे का रोषः आप क्या कर रही हैं मैडम राष्ट्रपति और मैडम गवर्नर?

मुंबई, 26 जुलाई (एजेन्सी)। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्य की राज्यपाल अनुसुइया उइके को संबोधित करते हुए सवाल उठाए।

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की एक और घटना अभी सामने आई है... ऐसी घटनाएं पहले भी हुई थीं। दुर्भाग्य से, तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। वीडियो सामने आने के बाद ही इन मामलों पर संज्ञान लिया गया और हो सकता है कि ऐसे कई और उदाहरण हैं।

उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा, 'देश में महिला राष्ट्रपति और मणिपुर में महिला राज्यपाल हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है।'

शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष ने कहा, 'मैं राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि आप एक महिला हैं, इसलिए देश में जो चल रहा है उस पर आपकी क्या भूमिका होगी? हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। अगर उस मां का अपमान किया जा रहा है और ऐसा तमाशा बनाया जा रहा है, तो एक महिला के रूप में आप क्या कर रही हैं, राष्ट्रपति महोदया?'

ठाकरे ने यही सवाल मणिपुर की राज्यपाल उइके से भी पूछे, जिन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी हिंसक घटनाएं कभी नहीं देखीं, जबकि यह मुद्दा फिलहाल संसद में गरमाया हुआ है।

ठाकरे ने कहा, 'तो, आप बस देख रही हैं... यह हैवानियत तीन महीने से चल रही है... आपकी भूमिका क्या है... ?'' उन्होंने कहा कि अत्याचार और क्रूरता सहने वाली महिला कारगिल युद्ध के नायक की पत्नी थी, जिससे यह और भी दु:खद हो गया।

उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्होंने राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने से पहले लगभग 36 सेकंड तक बात की।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने केंद्र और भाजपा का जिक्र करते हुए आगाह किया कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, लेकिन अब आशंका है कि यह टूट जाएगा। यहां तक कि 'डबल इंजन' सरकार भी बिखर गई है क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने पूछा, 'सरकार मणिपुर में ईडी या सीबीआई क्यों नहीं भेज रही है, क्योंकि इन केंद्रीय एजेंसियों की 'कुछ भी करने', सरकारों को नियंत्रित करने या यहां तक कि निर्वाचित शासन को गिराने की प्रतिष्ठा है...।'

गुरुवार को अपने 62वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सामना समूह के कार्यकारी संपादक सांसद संजय राउत को दिए गए वार्षिक मैराथन मल्टी-मीडिया साक्षात्कार में ठाकरे की तीखी टिप्पणियाँ आईं, जिसकी पहली किस्त बुधवार को प्रकाशित हुई है।

शिवसेना (यूबीटी) सुप्रीमो ने अपनी चेतावनी दोहराई कि मणिपुर के ज्वलंत परिदृश्य को देखते हुए, अगर भाजपा 2024 में सत्ता में लौटती है तो 'लोकतंत्र नहीं बचेगा', और देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। जम्मू-कश्मीर में छह साल

से चुनाव लंबित हैं।

उन्होंने मोदी और अमित शाह पर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया क्योंकि सब कुछ उनके नाम पर हो रहा है, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो या पार्टियों को तोड़ना और सरकारों को गिराना हो - स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र खतरे में है।

ठाकरे ने अपील की, 'हालांकि, मुझे लगता है कि 2024 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। देश के लोग उठेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। आम आदमी को सोचना नहीं चाहिए और वोट देना चाहिए... क्योंकि वह सिर्फ वोट नहीं दे रहा है, बल्कि अपना पूरा जीवन उनके हाथों में सौंप रहा है। ...वे (भाजपा) 10 साल से शासन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक पीढ़ी आगे बढ़ गई है। लोगों को अब आने वाली पीढ़ियों के लिए समझदार बनना चाहिए।'

राउत के इस सवाल पर कि क्या आधुनिक नेताओं की संवेदनाएं मर चुकी हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे हमेशा कहा जाता था कि 'राजनेताओं की चमड़ी गैंडे से भी अधिक मोटी होती है।'

ठाकरे ने मुस्कुराते हुए कहा, 'लेकिन, आजकल नेता कुछ ज्यादा ही मोटी चमड़ी वाले हो गए हैं... शायद गैंडा अपने बच्चों को बता रहा होगा कि उनकी चमड़ी इंसानी राजनेता जैसी है!'

मणिपर मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुए 6 विधेयक

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। लोकसभा में बुधवार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गयी।

कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने आज सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और सदन ने उसे चर्चा के लिए मंजूर किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बात करके और नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय तय करेंगे।

सदन में हंगामे के बीच ही सरकार ने छह विधेयक पेश किये।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। इस विधेयक को पेश किये जाने पर कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने आपत्ति प्रकट की।

गृह राज्य मंत्री राय ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 भी प्रस्तुत किये।

इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किये जाने का विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है और ऐसे में इस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस दौरान सदन में गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किये।

कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने खान और खनिज (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने इसे पेश किये जाने पर विरोध जताया।

मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सदन में बयान और फिर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की।

कांग्रेस के कुछ सदस्यों की नारेबाजी पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सदन की गरिमा रखें। यह भारत की संसद है। आप उसकी गरिमा गिराना चाहते हैं। आप सबसे पुराने दल हो, क्या इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है? इतने साल शासन में रहने के बाद आपको यह व्यवहार सिखाया गया है।

हंगामा जारी रहने पर उन्होंने दोपहर 12 बज कर करीब 17 मिनट पर सदन की बैठक दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस और भारतीय जवानों के शौर्य एवं पराक्रम का उल्लेख किया। पूरे सदन ने कुछ पल मौन रखकर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, उसी समय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर का मुद्दे उठाने लगे और नारेबाजी करने लगे।

विपक्षी सदस्यों ने सदन में जवाब दो-जवाब दो, प्रधानमंत्री सदन में आओ और वी वान्ट जस्टिस के नारे लगाए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद कर सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते? क्या आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते?

बिरला ने कहा, सदन की मर्यादा बनाकर रखें। यह सदन चर्चा के लिए है। हंगामा नहीं थमने पर बिरला ने पूर्वाह्न करीब 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मॉनसून सत्र के पहले चार दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई।

Justice N.K. Jain Judicial Inquiry Commission

(Constituted by Govt. of Sikkim, vide Notification No. 36/Home/ 2023 dated 12/07/2023)

No. 19/2023/L&PAD **Dated: 25/07/2023**

PUBLIC NOTICE

1. Hon'ble Justice Shri N.K. Jain (Retd), will be stationed in PWD Guest House at Namchi and will be available from 26th – 28th July, 2023 from 11.00 AM – 4.00 PM with a one hour lunch recess from 1.00 PM – 2.00 PM
2. Hon'ble Justice Shri N.K. Jain (Retd) shall be at Gangtok on 29th July, 2023 at the office of the State Human Rights Commission, Manan Kendra.
3. All the memers of Public are invited to share and submit any evidence (Audio, Video and other evidences) they may be possessing in connection with the death of Late Padam Gurung. All written statements should be given in sworn affidavits.

(Suraj Chettri)
Secretary to the Judicial Commission

R.O. No.: 100/IPR/PUB/Classi/2324, DT.: 25.07.2023

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR INDUS WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:17 DrawDate on:26/07/23 MRP ₹6/-
1st Prize ₹1 Crore/- 72C 44065
Cons. Prize ₹1000/- 44065 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
08426 22947 31828 37000 45378 48229 62094 76482 77054 98653
3rd Prize ₹450/-
0410 1212 2413 2507 2602 4623 5371 5653 6134 9880
4th Prize ₹250/-
0230 1609 3535 4048 6759 6979 8403 8839 9299 9648
5th Prize ₹120/-
0077 0110 0192 0250 0357 0437 0550 0791 0823 0953
0978 1097 1192 1215 1433 1506 1956 1967 2089 2167
2205 2303 2598 2677 2787 2910 2920 2973 3409 3508
3906 3976 3980 3982 4078 4098 4200 4241 4290 4311
4478 4528 4549 4566 4570 4612 4692 4849 5089 5282
5287 5335 5343 5416 5481 5482 5520 5682 5687 5785
5801 6082 6155 6303 6497 6731 6988 7052 7114 7137
7167 7208 7239 7306 7331 7432 7552 7786 7820 7956
8238 8242 8571 8831 9003 9081 9118 9126 9165 9304
9315 9326 9339 9495 9525 9556 9701 9733 9763 9901
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR HILL WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:17 DrawDate on:26/07/23 MRP ₹6/-
1st Prize ₹1 Crore/- 91B 13649
Cons. Prize ₹1000/- 13649 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
05140 07773 23912 25842 38191 51844 53422 69052 82393 95362
3rd Prize ₹450/-
2485 2886 3194 3562 5329 6107 6179 8066 9143 9524
4th Prize ₹250/-
0579 2991 3043 3519 4157 5493 6055 8384 8515 9937
5th Prize ₹120/-
0168 0373 0476 0529 0933 0988 1188 1189 1223 1254
1488 1602 1704 1912 2531 2562 2566 2603 2612 2809
2922 3109 3171 3198 3360 3435 3458 3555 3558 3587
3618 3678 3772 3853 4134 4240 4368 4378 4586 4955
5141 5156 5231 5459 5518 5520 5679 5784 5848 6078
6296 6493 6568 6712 7164 7237 7294 7352 7369 7490
7509 7572 7611 7619 7651 7691 7950 8184 8220 8269
8319 8357 8402 8405 8406 8495 8522 8541 8544 8680
8815 8919 9041 9117 9126 9212 9239 9401 9463 9497
9530 9540 9565 9587 9641 9679 9748 9939 9942 9947
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR PELICAN WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:17 DrawDate on:26/07/23 MRP ₹6/-
1st Prize ₹1 Crore/- 62G 21338
Cons. Prize ₹1000/- 21338 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
08856 23466 32920 34830 43999 47771 64724 68238 90475 91665
3rd Prize ₹450/-
2722 2947 4131 6149 6475 6979 7173 8033 8446 9602
4th Prize ₹250/-
1078 1995 2275 4684 5270 6270 7390 7601 7602 9697
5th Prize ₹120/-
0422 0817 0875 0980 1050 1066 1105 1152 1182 1307
1409 1451 1507 1540 1631 1789 1901 1945 2003 2128
2154 2333 2340 2389 2585 2625 2679 2702 2901 2929
2977 3194 3202 3215 3805 3860 4000 4094 4194 4339
4344 4470 4589 4643 4693 4861 4938 4985 5068 5102
5157 5199 5281 5320 5347 5625 5772 5773 5830 5923
5946 6068 6431 6488 6496 6514 6536 6678 6914 6933
6981 7109 7126 7170 7212 7277 7351 7363 7396 7429
7658 7814 7882 7915 8111 8291 8503 8541 8600 8653
8886 9012 9086 9343 9492 9499 9682 9762 9828 9866
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

लोकतंत्र पर हमला

इस्राइली संसद ने सोमवार को वह रीजनेबलनेस बिल पास कर दिया, जिसे कथित न्यायिक सुधार का पहला चरण बताया जा रहा है। यह बिल नेतन्याहू सरकार की जुडिशरी को कमजोर करने की विस्तृत योजना का हिस्सा है और इसके खिलाफ वहां पिछले करीब छह महीने से व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में बिल पास किए जाते समय विपक्ष मौजूद नहीं था, इसीलिए 64-0 से पास हो गया। लेकिन संसद के बाहर सड़कों पर उस समय भी हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि नेतन्याहू सरकार इस बिल को जुडिशरी पर हमला नहीं मानती। उसके मुताबिक, यह देश के अंदर सत्ता समीकरण को फिर से संतुलित करने की कोशिश है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पावर इक्वेशन को रीबैलेंस करने के नाम पर सरकार ने जुडिशरी के अधिकार कम किए हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद न्यायपालिका को सरकार के फैसलों की समीक्षा करके उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। जाहिर तौर पर यह एक निर्वाचित सरकार द्वारा देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का ऐसा मामला है, जिसे दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों और समाजों के लिए चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए।

किसी जमाने में वामपंथी विचारधारा को लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथ की तेजी से उभरती प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बनती दिख रही हैं। ऐसे में इसे हलके में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस्राइल के सबसे करीबी देशों में गिने जाने वाले अमेरिका ने भी उसे ऐसे विधेयकों पर जल्दबाजी न करने और आम सहमति बनाने का सुझाव दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, नेतन्याहू को भेजे संदेश में यहां तक कह चुके हैं कि इन बिलों को पारित करने पर जोर देकर उनकी सरकार दोनों देशों के रिश्ते को दांव पर लगा रही है। लेकिन खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू ने सभी सुझावों को दरकिनार करते हुए जुडिशरी के पर कतरने का अपना अजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पहले तो यह देखना होगा कि इस्राइल में इसके किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। इसे जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है वहीं इसके खिलाफ व्यापक हड़ताल की भी चेतावनी दी जा रही है।

नेतन्याहू सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और वहां घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दुनिया भर की लोकतांत्रिक शक्तियां इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लें। हालांकि यह ऐसी लड़ाई है, जिसे हर लोकतांत्रिक समाज को अपने स्तर पर और खुद लड़ना होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की भी इतनी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि ऐसे मामलों में वह अपने नैतिक समर्थन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करे।

फार्मा क्षेत्र की साख, गुणवत्ता में हानि से विश्व बाजार में धूमिल हो रही भारत की प्रतिष्ठा

वरुण गांधी

जनवरी, 2020 में हिमाचल प्रदेश स्थित डिजिटल विजन द्वारा निर्मित दवा कोल्डबेस्ट पीसी कफ सिरप का सेवन करने के बाद जम्मू में 12 बच्चों की मौत हो गई। उस दवा में डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जिससे किडनी में जहर फैल जाता है। गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बावजूद डिजिटल विजन को विभिन्न राज्यों और केंद्रीय दवा प्रयोगशालाओं द्वारा 19 मौकों पर हरी झंडी दी गई थी। उस घटना के बाद हिमाचल के राज्य नियामक ने भी मौके पर किए गए निरीक्षण में दवा बनाने में गुणवत्ता का दोष पाया।

छह महीने बाद इसी कंपनी के एक और उत्पाद के सेवन से हिमाचल के एक बच्चे की मौत हो गई। मार्च, 2021 में एक और दवा में परीक्षण एजेंसियों द्वारा सक्रिय संघटक के निम्न स्तर पाए गए। इतने पर भी दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई बहुत प्रभावी नहीं रही। ऐसे मामलों में दवा निर्माताओं के खिलाफ मामला बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है। देश में 36 ड्रग रेगुलेटर हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।

भारत विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है। वैश्विक फार्मा बाजार में हमारी हिस्सेदारी 13 फीसदी है और हम 200 से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति करते हैं। टीकों के मामले में तो हमारी वैश्विक हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। इस तरह भारत दुनिया भर में गरीबों के जीवन में बदलाव की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। फार्मा सेक्टर के विकास के लिए उद्यमियों ने लंबा संघर्ष किया है। पर निर्यात बाजार में दवा नियमों और भारतीय दवाओं के अप्रभावी या हानिकारक होने की अपमानजनक घटनाओं से इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। 48 आम दवाएं हाल ही में गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही हैं। उच्च रक्तचाप, एलर्जी और जीवाणु संक्रमण के लिए भारतीयों द्वारा नियमित रूप से ली जाने वाली तमाम दवाओं का करीब तीन प्रतिशत विनियामक निरीक्षकों की नमूना जांच में घटिया पाया गया है।

विगत फरवरी में तमिलनाडु की एक फर्म ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर द्वारा अमेरिका को निर्यात किए गए आई ड्रॉप्स के एक पूरे बैच को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता था। मैडान फार्मास्यूटिकल्स और मैरियन बायोटेक द्वारा देश में बनाए गए कफ सिरप को 2022 में क्रमशः गांबिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से जोड़ा गया था। हालांकि भारत के ड्रग रेगुलेटर ने ऐसे किसी संबंध से इन्कार करते हुए कहा कि इसकी सैंपल जांच में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया है।

दवाओं की गुणवत्ता मामलों का निजी और सामाजिक, दोनों ही तरह का असर पड़ सकता है। कई बार एजिथ्रोमाइसिन जैसी सामान्य दवा कम प्रभावी पाई गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) द्वारा 20 राज्यों की 76 फर्मों के निरीक्षण के बाद 18 फार्मा कंपनियों के विनिर्माण लाइसेंस रद्द करने के साथ केंद्र सरकार दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठा रही है। वैसे अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस बीच, वैश्विक नियामकों की कार्रवाई भी जारी है। नवंबर, 2019 से विगत नवंबर तक यूएस एफडीए ने 60 आधिकारिक कार्रवाइयों (ओएआई) के बारे में संकेत दिए हैं। एफडीए के चुनिंदा निरीक्षणों में पाया गया है कि कुछ बड़े फार्मास्यूटिकल खिलाड़ियों द्वारा खासकर कैंसर संबंधित और इंसुलिन दवाओं के निर्माण में माइक्रोबायलॉजिकल संदूषण को रोकने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामलों में फंगल से बचने के तरीके तक अमल में नहीं लाए जा रहे। दवाओं की गुणवत्ता के मामले में ऐसी लापरवाही खतरनाक है, जिससे दुनिया में भारत की साख प्रभावित हो रही है।

जाहिर है कि फार्मा क्षेत्र में ठोस विनियामकीय सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय सभी फार्मा निर्माताओं पर प्रभावी निगरानी के लिए दवाओं के केंद्रीकृत डाटाबेस को बढ़ावा देने की पहल के साथ ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट (1940) में संशोधन कर सकता है। यदि संघीय-राज्य सहयोग इसकी अनुमति देता है, तो देश के 36 क्षेत्रीय नियामकों को एक एकल नियामकीय व्यवस्था की शक्ल दी जा सकती है। इससे स्थानीय व राज्य स्तर पर नियामकीय प्रक्रिया को प्रभावित करने के जोखिम न्यूनतम हो जाएंगे।

नियामकीय सशक्तता के लिए राज्यों में सामान्य दवा मानकों की भी जरूरत है। देश में 10,000 से अधिक दवा निर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से 2,000 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रामाणिक पाया है। ऐसी इकाइयां 3,000 से अधिक फर्मों के स्वामित्व में हैं, जिनमें हजारों उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी को विनियमित करने का अर्थ है- निरीक्षण की एक बड़ी जवाबदेही। अतीत में नियमित जांच के दौरान महज सक्रिय अवयवों की कमी पर रोशनी डाली गई है। 2013 में तमिलनाडु में एक एंट्री एलर्जिक दवा को सिर्फ ग्लिपीजाइड का इस्तेमाल न होने के कारण गैरमानकीय करार दिया गया था। राज्य दवा नियंत्रकों के तहत निरीक्षण टीमों को मजबूत करने और निरीक्षण अवधि को कम और नियमित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता की जरूरत है।

भारत में बनी दवाओं के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए नियामकीय प्रक्रिया का पारदर्शी और प्रभावी होना जरूरी है। इसके अलावा हमें पिछली गंभीर नियामकीय व गुणवत्ता संबंधी उल्लंघनों का डाटाबेस भी सार्वजनिक करना चाहिए। ड्रग रिकॉल पर एक राष्ट्रीय कानून के लिए भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह प्रस्ताव 1976 से लटका पड़ा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का वैधानिक सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए और इसके लिए स्वतंत्र निकाय के रूप में एक केंद्रीय औषधि प्राधिकरण बनाने के लिए ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स (संशोधन) विधेयक, 2013 की तरह एक बिल तैयार व पारित करना चाहिए।

देश के विश्व प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल उद्योग को साधारण जेनेरिक दवाओं के निर्माण से आगे गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक व नवोन्मेषी दवाओं के निर्माण से जुड़े उद्योग की ओर बढ़ना चाहिए। इक्वाडोर, पनामा और नाइजीरिया जैसे देशों ने हाल ही में भारतीय जेनेरिक दवाओं में अपनी बढ़ी दिलचस्पी जाहिर की है। भारत सरकार ने शून्य दोष के साथ 'मेक इन इंडिया' की बात की है। इसी आलोक में देश के दवा उद्योग से जुड़ी चुनौती पर खरा उतरने के लिए संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना होगा।

एनडीए बनाम इंडिया

प्रेमकुमार मणि

वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों की देर है, इसलिए स्वाभाविक है पक्ष-विपक्ष राजनीतिक मोर्चेबंदी पूरी कर लें।

2004 से 2014 के बीच कांग्रेस केंद्र सरकार में बनी हुई थी, तब उसने न तो अपने सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त किया और न यूपीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल ठीक रखा। कम्युनिस्टों से तो कुछ पहले ही अनबन हो गई थी, उत्तर भारत के अनेक दल भी उसके प्रति उदासीन हो गए। राजद, लोजपा, तृणमूल आदि की दूरी कांग्रेस से बढ़ती गई। डॉ. मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी पर किसी को शुबहा नहीं हुआ, किंतु टूजी और कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले पर भ्रष्टाचार के मामले बोफोर्स मामले की तरह ही चर्चा के विषय बन गए। इन सब बातों का नतीजा हुआ कि 2014 में कांग्रेस 44 पर सिमट गई। वामदलों ने भी अपनी प्रभावकारी स्थिति खो दी। दूसरे गैर-भाजपा क्षेत्रीय दल भी अपने अंतर्विरोधों से बहुत कमजोर गए। लगभग यही स्थिति 2019 में भी बनी रही। इसलिए स्वाभाविक हैं कि 2024 चुनाव के पूर्व कांग्रेस और गैर-भाजपाई दल एकजुट और गोलबंद हों। 2014 के मुकाबले 2019 भाजपा ने छह फीसद वोट अधिक हासिल किए थे। उसने ऐसी ही रफ्तार बनाए रखी या उससे नीचे नहीं गिरी तो उसे पराजित करना मुश्किल होगा। ऐसे में स्पष्ट है कि गैर-भाजपा दलों की गोलबंदी ही भाजपा को रोक सकती है।

इस बार एकता की मुहीम बिहार से आरंभ हुई। 2022 अगस्त में बिहार में राजनीतिक अफरा-तफरी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना सुगबुगाहट या पूर्वसूचना एक रोज भाजपा के खिलाफ पलटी मारी और अपने धुर विरोधी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। कुछ इसी तरह उन्होंने पांच साल पूर्व 2017 में राजद से हट कर भाजपा के साथ गठबंधन साध लिया था। दोनों बार नीतीश की छवि को धक्का जरूर लगा, लेकिन जिनके साथ वे गए उन्हें राजनीतिक फायदा हुआ। 2017 में भाजपा के साथ होने का राजनीतिक प्रतिफल यह निकला कि 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटें हासिल कर लीं। 2022 में उनके राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ होने पर कुछ लोगों का अनुमान है कि वैसे ही नतीजे प्राप्त होंगे।

इसी उत्साह ने नीतीश को राजनीतिक रूप से ऐसा सक्रिय किया कि वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिपक्ष की गोलबंदी के अभियान में जुट गए। पिछले जून महीने में उनके प्रयास से पटना में सोलह प्रतिपक्षी दलों की बैठक हुई। उसकी अगली कड़ी के रूप में पिछले 18 जुलाई को बेंगलुरू में 26 गैर-भाजपा दलों की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का नया रूप इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (संक्षिप्त रूप इंडिया) रखा गया।

ठीक इसी रोज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का भी पुनर्गठन हुआ जिसमें इस बार 38 दल शामिल हुए। इस तरह देखा जाए तो आने वाले चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच सीधी लड़ाई संभावित है। एक समय कांग्रेस और हाल के दिनों में भाजपा भी क्षेत्रीय दलों को हिकारत की नजर से देखती थी लेकिन आज राजनीतिक मजबूरी है कि उपरोक्त दोनों दलों को क्षेत्रीय दलों की जरूरत है। कांग्रेस तो खैर राजनीतिक तौर पर अभी खस्ता हाल है, किंतु भाजपा, जो केंद्र में पूर्ण बहुमत में है, को इलाकाई दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक उपयोगिता आने वाले समय में और बढ़ सकती है। अनुमान है भारतीय लोकतंत्र जितना अधिक लोकसत्तात्मक होगा, क्षेत्रीय दल उतने ही अपरिहार्य होते जाएंगे। इसलिए पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ इन दलों का ध्रुवीकरण हमारे लोकतंत्र के लिए शुभता का प्रतीक है। हां, इनका बिखरे रूप में चुनाव लड़ना और चुनाव बाद का मोल तोल ठीक नहीं होता है। आने वाले चुनाव में सबकी नजर इंडिया गठबंधन की तरफ होगी। लेकिन बेंगलुरू से जो संदेश मिला है वह बहुत उत्साहजनक नहीं है। भाजपा को हिन्दीभाषी राज्यों में पराजित करना उसके लिए मुख्य चुनौती होगी। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ,दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा को पराजित किए बिना केंद्र से उसे विस्थापित करना मुश्किल होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस ने उस तरह लक्ष्य नहीं किया, जिस तरह भाजपा ने किया। एनडीए में बिहार और यूपी के प्रतिपक्षी महागठबंधन के कई चेहरे दिखे। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, राजभर जैसे भाजपा विरोधी कैंप के लोग आज यदि एनडीए के साथ हैं, तो इसे भाजपा की रणनीतिक सफलता ही कहेंगे।

आखिर कांग्रेस इन्हें अपने साथ रख क्यों नहीं सकी। बिहार और यूपी में लालू-नीतीश-अखिलेश के खिलाफ दलितों, अत्यंत पिछड़ी जातियों और सवर्ण कही जाने वाली जातियों में आक्रोश है, जिसका वोटों में प्रदर्शन होता रहा है। यह जरूर है कि इस बीच मुसलमानों और दलितों के बीच कांग्रेस के लिए आकर्षण विकसित हुआ है लेकिन जब कांग्रेस लालू-नीतीश-अखिलेश के दलों के साथ गठबंधन में होगी तो इन प्रांतों में उसे सीटें कम मिलेंगी। और वर्तमान परिस्थितियों में राजद-जदयू-सपा द्वारा भाजपा का मुकाबला बहुत असरदार नहीं होगा।

अगले चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस को हिन्दी इलाकों में अपने को मजबूत करना होगा। कांग्रेस नेता बार-बार विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन हिन्दी क्षेत्रों में इस लड़ाई का विस्तार देते नहीं दिखते। लालू, नीतीश, अखिलेश के लोकदली मानस के साथ वे इस लड़ाई की संगत स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि इन दलों के साथ उनका बुनियादी वैचारिक विरोध है। केवल भाजपा विरोध पर वे एकमत हैं। कांग्रेस ने इन्हें अलग-थलग कर इन राज्यों में चुनाव लड़ा तो भाजपा को कारगर शिकस्त दे सकती है। लेकिन इसके पूर्व उसे अपने ढांचे का परिमार्जन करना होगा। दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वगरे के एक हिस्से के साथ कांग्रेस ही सवर्ण कही जाने वाली जातियों के वोट हासिल कर सकने में सक्षम हो सकती है। सवर्ण वोट इन राज्यों में लगभग एकमुश्त भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनके बीच भाजपा की आलोचना तीखे अंदाज में विकसित हुई है। लालू, नीतीश, अखिलेश के साथ ये वोट प्रभावकारी रूप में नहीं आ सकते। लेकिन यह बड़ा फैसला होगा जिसे इंदिरा गांधी तो ले सकती थीं, खड़गे और राहुल गांधी लेंगे इसमें संदेह है।

पहाड़ में बदलती खेती

नरेन्द्र सिंह बिष्ट

वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। जलवायु में होने वाले बदलावों ने सबसे अधिक कृषक वर्ग को प्रभावित किया है, चाहे वह मैदानी क्षेत्र के किसान हों या फिर पर्वतीय क्षेत्र के। मैदानी क्षेत्र में फिर भी आजीविका के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का खामियाजा कृषकों को ज्यादा ही उठाना पड़ता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के पास आय के दूसरे स्रोत नहीं हैं। वहीं प्राकृतिक कहर और जंगली जानवरों के नुकसान ने किसानों को खेती से विमुख होने के लिए विवश कर दिया है। अब किसान या तो पलायन के लिए मजबूर हैं या फिर मामूली तनख्वाह पर कहीं काम कर रहे हैं।

लेकिन इन कठिनाइयों के बीच नितिन महतोलिया और मनोज बिष्ट जैसे कुछ युवा किसानों ने हार नहीं मानी और खेती के ऐसे स्वरूप को अपनाया, जो अब उनके उज्ज्वल भविष्य की आस के रूप में दिखाई देने लगा है। उन्होंने कम समय में अधिक उत्पादन व नकदी खेती की ओर रुझान किया, जिसमें मशरूम, औषधीय पौधे व पॉलीहाउस खेती प्रमुख हैं। इनमें जंगली जानवरों का खतरा व मौसम की मार का प्रभाव न के बराबर होता है।

कृषि कार्य में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए नैनीताल के महतोलिया गांव के युवा किसान नितिन ने अलग प्रकार से खेती करने का मन बनाया और पॉलीहाउस के जरिये फूलों की खेती शुरू की। उन्होंने गांव में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में पॉलीहाउस की जानकारी ली। प्रथम वर्ष में ही पॉलीहाउस में लागत और मेहनताना के अलावा उन्हें 20,000 रुपये का लाभ हुआ। जो खेत अनाज उगाने में असमर्थ हो गए थे, वही आज नितिन को प्रति सीजन एक लाख रुपये की आय दे रहे हैं। नितिन के पॉलीहाउस में उगाए गए फूल आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली तक बेचे जा रहे हैं। नितिन अब गांव के अन्य युवाओं को भी इस ओर प्रेरित कर उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे पलायन की जगह घर पर ही रहकर आय सृजित कर सकें।

पॉलीहाउस की खेती के संबंध में भीमताल ब्लॉक के सहायक उद्यान अधिकारी आनंद सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार द्वारा ग्रामीण समुदाय के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से एक पॉलीहाउस खेती भी है। इस वर्ष नैनीताल में 23,000 वर्ग मीटर पर जिला एवं केंद्र योजना के अंतर्गत 163 लोगों को पॉलीहाउस खेती से लाभान्वित किया गया, जिसमें सब्जी और फूलों की खेती की जा रही है।

नितिन की तरह ही अल्मोड़ा स्थित लमगड़ा के युवा किसान मनोज बिष्ट ने पारंपरिक खेती से अलग मशरूम की खेती करने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें घर वालों के विरोध का सामना करना भी पड़ा। लेकिन मनोज ने उनकी बातों को नकारते हुए इसमें सफलता हासिल की। आज उनका मशरूम हल्द्वानी, नैनीताल व अल्मोड़ा में बिक रहा है। उनके द्वारा गांव के 12 लोगों को रोजगार भी मिला है। उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से विश्व में अपनी खास पहचान रखता है, जिसके चलते लाखों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष यहां आते हैं, उनके खाने में मशरूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके चलते भीमताल को मशरूम उत्पादन का हब बनाने को लेकर जिला प्रशासन की योजना कामयाब हो रही है।

खाने में विशेषता उपलब्ध कराने के साथ-साथ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश में भीमताल विकास खंड के सोनगांव, भवाली व नथुवाखान क्लस्टर का गठन किया गया, जिसमें वर्ष 2022-23 में 131 लाभार्थियों को 156 बीजयुक्त मशरूम कंपोस्ट उपलब्ध करवाए गए। वास्तव में, सरकारी योजनाएं लोगों के हित में बनाई जाती हैं, जिससे युवाओं को काफी लाभ भी मिलता है। पर परियोजना समाप्ति के पश्चात रख-रखाव से संबंधित कोई विधि न होने के बाद अक्सर कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ देती हैं। ऐसे में सरकार और संबंधित विभाग को ऐसी योजनाएं बनाने की जरूरत है, जिससे परियोजना समाप्ति के बाद भी योजनाएं निर्बाध गति से चलती रहें। इसके लिए स्वयं लाभान्वितों को भी आगे आने की जरूरत है, ताकि इसका फायदा उनके साथ-साथ अन्य बेरोजगार युवाओं को भी मिले।

फैशन की रिमझिम

मौसम है गर्मी और आर्द्रता का तो कपड़े भी होने चाहिए उसके अनुकूल। इस मौसम में भारी और सजावटी सिल्क व ब्रोकेड के परिधानों से दूरी बनाएं और अपनाएं मलमल, सॉफ्ट कॉटन और जूट के परिधान पहनें।

नेचुरल फाइबर

गर्मी में नेचुरल फाइबर से बने कॉटन और जूट के परिधानों से बेहतर कुछ भी नहीं। ये त्वचा को सांस लेने में मदद करते हैं। साथ ही गर्मी के कारण त्वचा पर चकत्ते पड़ने और एलर्जी होने की समस्या से भी मुक्ति दिलाते हैं। गर्मी के मौसम में सिंथेटिक परिधानों से बचना चाहिए। चिकन के कपड़े भी गर्मी के लिहाज से अच्छे हैं। वहीं चिकनकारी के काम से सजे परिधान भव्य भी लगते हैं। गोसामर क्वालिटी चिकन आपको कई तरीके से कूल रखता है।

फ्लोरल प्रिंट

शार्ट स्कर्ट और शा ?र्ट्स पहनने का यही है मौसम। उनके साथ मैच करें स्ट्रैपी ब्लाउज। इस तरह बन जाएगा आपका कूल फैशन स्टेटमेंट। फ्लोरल प्रिंट में डेलीकेट और फ्लोइंग ड्रेस भी गर्मी के इस मौसम में अच्छी लगेंगी। प्लेफुल वाटरकलर प्रिंट्स भी गर्मी में लगते हैं बेहतरीन।

स्लीवलेस स्टाइल

एथनिक व पांपरिक कढ़ाई से सजी स्लीवलेस चोली भी है गर्मी के फैशन का हिस्सा। उसके संग चुनें एथनिक लुक वाली साड़ी और आप बन जाएंगी हर पार्टी की जान।

कलर्स

यह माना जाता है कि गर्मी में हल्के और पेस्टल कलर अच्छे लगते हैं, पर ब्राइट कलर्स का चुनाव भी है एक अच्छा आइडिया। ब्राइट रेड, फ्यूशिया, लीफ ग्रीन, कनारी यलो, ऑरेन्ज और पिंक कलर से बनेगी बात।

डेनिम

डेनिम के साथ मैच करें फ्रूटी शेड्स में फिटिंग के टॉप। इसके अलावा खूबसूरत पारंपरिक रंगों में एथनिक कुर्ती भी डेनिम के साथ स्मार्ट लुक देगी। आप खूबसूरत लेस वाले टॉप भी चुन सकती हैं।

हल्के फैब्रिक

बेहद हल्के फैब्रिक पुरुषों के लिए भी हैं कूल और एलीगेंट चॉइस। हल्के फैब्रिक और चटख रंग की श ?र्ट्स के साथ लिनेन की पैंट्स आकर्षक लगेगी।

ऑफिस

फॉरमल वेयर को भी आप कूल बना सकते हैं। लिनेन, कॉटन, जूट जैसे नेचुरल फाइबर्स चुनें। दिन के लिए स्ट्राइप्स, डॉट्स और पेस्टल शेड्स हैं परफेक्ट।

ईवनिंग वेयर

बारबेक्यु या बीच पार्टी के लिए स्टाइल और खूबसूरत रंगों से करें अपने ड्रेसिंग सेंस को कंप्लीट। कूल टीशर्ट के साथ विंटेज जींस, लिनेन शॉर्ट्स के साथ फ्लोरल प्रिंट्स, मुसलिन की झीनी शर्ट्स के साथ जूट की पैंट्स आपको मौसम के अनुकूल कूल लुक देगी।

एक्सेसरीज

बीड्स, ब्रेसलेट्स और चार्म सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि लड़कों के लिए भी हैं स्मार्ट एक्सेसरी। मौसम के मिजाज के अनुकूल परिधान के संग बेरी कलर का ब्रेसलेट परफेक्ट लगेगा। वहीं लड़कों को दिखना है स्टाइलिश तो वे अपना सकते हैं लेदर के साथ बीड्स ब्रेसलेट और गले में सिल्वर चेन। एक्सेसरीज ऐसी चुनें जो बहुत भारी न हों। याद रखें हल्की और स्टाइलिश एक्सेसरीज ही लगेगी अच्छी।

स्कार्फ

फ्लोरल प्रिंट्स, फ्रूटी कलर्स, हल्के व फ्लोइंग का है फैशन। गर्मी के मौसम में स्कार्फ चुनते वक्त उपरोक्त बातों का रखें ध्यान। इसे आप सी-बीच, पार्टी या ऑफिस कहीं भी पहन सकती हैं। सभी जगहों पर स्कार्फ अच्छा लगेगा।

खुद बनाएं मनपसंद हेयर स्टाइल

आपको पार्टी में जाना है और हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाने का वक्त नहीं है! ऐसी स्थिति से महिलाएं अकसर दो-चार होती हैं। समय की कमी के चलते अकसर हमें अपने हेयर स्टाइल को इग्नोर करना पड़ जाता है। फिक्र न करें। जावेद हबीब आपको बता रहे है कुछ आसान और क्विक हेयर स्टाइलिंग के टिप्स जिससे आप बालों की स्टाइलिंग खुद कर सकती हैं।

1. अगर आपको वेवी लुक पसंद है तो बस हेयर ब्रश, टेक्सचराइजिंग क्रीम और हेयर ड्रायर के सहारे आप अपने बालों को वेवी लुक देकर उनमें वॉल्यूम पैदा कर सकती हैं।

2. अगर आपको स्ट्रेट हेयर लुक चाहिए तो शॉवर के बाद अपने बालों को तौलिये से सुखा लें। फिर टेक्सचराइजिंग जेल को उंगलियों में लगाकर बालों की लटों में फैलाएं और कंघी करें। इससे आपके बाल सुलझे और स्ट्रेट दिखेंगे।

3. बालों को बाउंसी लुक देने के लिए सिर झुकाकर उन्हें पलट कर ब्लो ड्राई करें। करीब दस मिनट तक पलटे हुए बालों में कंघी करने से बालों में अच्छा बाउंस आ जाता है जो आपको फ्लैट और बोरिंग लुक से निजात देता है।

4. अपने बालों में खुशबू पैदा करने के लिए कंघी या हेयर ब्रश पर अपना मनपसंद परफ्यूम स्प्रे करें। इससे बाल सुलझाने पर बालों में महक आनी शुरू हो जाएगी जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित जरूर करेगी।

5. बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे शैंपू और कंडीशनर का प्रयोग भी जरूरी होता है। ज्यादातर शैंपू व कंडीशनर इतने गाढ़े होते हैं कि सिर की त्वचा पर जम जाते है और अच्छी तरह से साफ भी नहीं होते। ऐसे गाढ़े शैंपू या कंडीशनर्स को प्रयोग करने से पहले पानी डालकर पतला कर लें।

6. घर में सलून जैसी हेयर स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले बालों को छोटे-छोटे सेक्शंस में बांट लें। हॉट रोलर्स, ब्लो ड्रायर और स्टाइलिंग जेल के साथ इनमें से एक-एक सेक्शन को कर्ल करें, बेहतरीन हेयर स्टाइल तैयार हो जाएगा।

स्पा का है यह सीजन

स्पा के लिए सबसे बेहतर मौसम है मानसून। वातावरण में घुली नमी, शीतलता और हवा में स्वच्छता के मध्य स्पा से शरीर को मिलती हैं ऐसी ताजगी, जो किसी और मौसम में मुमकिन नहीं.. अगर बात मानसिक शांति और तनाव मुक्ति की हो रही हो और स्पा का जिक्र न हो तो बात अधूरी ही मानी जाएगी। स्पा से आशय है सेनस पर एक्रम से। जिसका अर्थ है जल के इस्तेमाल से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया। यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में बेल्जियम में हुई थी। धीरे-धीरे इसका चलन पूरे यूरोप में फैल गया। इसके तौर-तरीकों में भी बदलाव हुआ। कुछ स्थानों पर स्पा में मिनरल्स और समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं पर अन्य समुद्री सामग्री के माध्यम से शरीर को तनावमुक्त और स्फूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को स्पा कहते हैं। हालांकि आज इसके मायने काफी हद तक बदल चुके हैं। यह लोगों को मौका देता है तनाव दूर करने का, ब्यूटी ट्रीटमेंट का, हाथ और पैरों को संवारने का, वह भी कुदरत के माध्यम से।

क्या हैं फायदे

- स्पा थैरेपी शरीर में ऑक्सीजन के साथ ही रक्त के प्रवाह को तेज करके तनाव और थकान दूर करने में मदद करती है।
- स्पा थैरेपीज मस्कुलर , स्केलेटल , सर्कुलेटरी , रेस्पिरेटरी , एंडोक्राइन (अंतःस्रावी), लिम्फेटिक (लसीका संबंधी) और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ ही भावनात्मक और मानसिक तौर पर भी शांति प्रदान करती हैं। इससे थकान, उदासी दूर होने के साथ ही मांसपेशियों में भी मजबूती आती है।
- स्पा बॉडी मसाज ब्लड प्रेशर कम करने के साथ ही प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह मसाज तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर कम करता है और दिमाग को शांति पहुंचाने वाले हारमोन्स जैसे सेरेटोनिन के स्राव का स्तर बढ़ाता है।

बॉडी रैप और मड बाथ भी स्पा के दूसरे प्रसिद्ध ट्रीटमेंट हैं। यह त्वचा के टेक्सचर को बेहतर बनाने के साथ ही त्वचा में नई रंगत पैदा करते हैं। बॉडी रैप शरीर को डीटॉक्सीफाई, टेंपरेरी इंच लॉस, त्वचा में कसाव और कोमलता लाने के साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम और मेटॉबालिज्म स्तर को सुधारता है। वहीं मड थैरेपी त्वचा में कसाव लाने, उसकी सफाई करने, चमकदार बनाने के साथ ही उसे एक्सफॉलिएट भी करती है। आजकल स्पा थैरेपीज के साथ बोटॉक्स और फिलर्स का कॉम्बीनेशन जिन्हें मेडी स्पा कहते हैं लोगों को रिझा रहे हैं।

समय हो सही

मानसून स्पा के लिए सबसे बेहतर मौसम इसलिए है, क्योंकि इस दौरान मौसम तो नम होता ही है। साथ ही हवा में धूल-मिट्टी भी कम होती है। इस मौसम में शरीर के सूक्ष्म छिद्र आसानी से खुल जाते हैं और ट्रीटमेंट और बेहतर हो पाता है। लगभग तीन माह में एक बार अपने दोस्तों या पति के साथ स्पा का मजा जरूर लें। हां, पैडीक्योर और मैनीक्योर हर महीने कराती रहें। स्पा में सामान्य तौर पर मिलने वाली सर्विस के अलावा आप जैली रब, एरोमैटिक एक्सफॉलिएटिंग स्क्रब, हाइड्रेटिंग मास्क, हॉट टॉवेल रैप, पैराफिन डिप के अलावा कई चीजों का आनंद ले सकती हैं।

क्या न करें

- ट्रीटमेंट के कम से कम एक घंटे के बाद ही किसी चीज का सेवन करें। इसी प्रकार यदि आपने कुछ खाया है तो करीब एक-डेढ़ घंटे बाद ही स्पा का रुख करें।
- यदि पैरों में कट या कोई चोट है तो फिश पैडीक्योर न कराएं। यह खतरनाक इन्फेक्शन पैदा कर सकता है।
- कभी भी खुले लूफाह का इस्तेमाल न करें।
- यदि आप क्लॉस्ट्रोफोबिया (किसी स्थान पर बंद हो जाने को लेकर भय) के शिकार हैं तो रैप और स्टीम थैरेपीज से बचें।
- सोराइसिस और डर्मेटाइटिस जैसी किसी भी तरह की त्वचा संबंधी समस्या होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के स्पा ट्रीटमेंट से दूर रहें।

ध्यान रखें

- किसी भी स्पा ट्रीटमेंट का लाभ उठाने से पहले उस संस्थान के परिचय पत्र के साथ ही उसकी संपूर्ण जानकारी अवश्य लें।
- बुकिंग कराने से पहले अपनी जरूरत के बारे में थैरेपिस्ट से विस्तृत चर्चा अवश्य करें।
- यदि आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो आयोडीन और मड ट्रीटमेंट से एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतें। यदि ट्रीटमेंट के दौरान खुजली महसूस हो तो फौरन ही ट्रीटमेंट बंद कर दें।
- कॉस्मेटिक या डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर के अनुभव के बारे में जानकारी अवश्य जुटा लें। इसके लिए उन लोगों से बातचीत कर सकती हैं जो वहां ट्रीटमेंट ले चुके हों।

कलर ऑफ द ईयर मारस्ला

फैशन की दुनिया में रंगों का भी अलग महत्व है। इस बार ट्रेंड बनकर उभरा है मारस्ला कलर। फैशन जगत की नामचीन हस्तियों ने इसे दिया है कलर ऑफ द ईयर का खिताब। दरअसल ड्रेस, फैशन एक्सेसरीज से लेकर होम फर्निशिंग तक सभी में इसका जादू छाया है। रेड और ब्राउन के मिक्स से बना मारस्ला कलर देता हैं एलीगेंट लुक। इसके साथ ही ये देता है आत्मविश्वास और स्थिरता का संतुष्टि भरा अहसास। परिधानों के मामले में सिल्क और शिफॉन जैसे रिच फैब्रिक इस कलर का ग्रेस बढ़ाते हैं। इस कलर की ड्रेस का चुनाव करने जा रही हैं तो परफेक्ट मिक्स एंड मैच का ख्याल रखें। मारस्ला कलर की ड्रेस के साथ स्कार्फ किसी अन्य कलर का चुन सकती हैं। जहां तक एक्सेसरीज की बात है हैंडबैग, फुटवेयर, बेल्ट इत्यादि में टॉप पर है मारस्ला। इस कलर की एक्सेसरीज को भी आप बना सकती हैं अपना स्टाइल स्टेटमेंट। वहीं मेकअप प्रोडक्ट्स में भी इस रंग का जवाब नहीं। खास बात यह है कि आपकी रंगत कैसी भी हो, सभी पर जंचती है मारस्ला कलर की नेलपॉलिश व लिपस्टिक। नेलपॉलिश में गोल्डन से नेल आर्ट बेहद आकर्षक लगेगी। होम फर्निशिंग की बात करें तो मारस्ला कलर में लेदर के सोफे से लेकर वॉल पेंट तक कुछ भी चुन सकती हैं, किसी भी रूप में मारस्ला का स्पर्श आपके घर को देगा क्लासी लुक। अब देर किस बात की कलर ऑफ द ईयर को अपनाकर निखारें अपना घर और व्यक्तित्व दोनों।

न्यूज

कम्बोडिया में सीपीपी को आम चुनाव में भारी बहुमत

नोम पेन्ह, (एजेंसी)। कम्बोडिया में सत्तारूढ़ कम्बोडियन पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) को आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल हुआ है। सीपीपी को आम चुनाव में 120 संसदीय सीटों पर जीत मिली जबकि रॉयलिस्ट फनसिनपेक पार्टी शेष पांच सीटें ही जीत पायी है। 125 सीटों वाली नेशनल असेंबली के लिए इस आम चुनाव में कुल 18 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय चुनाव समिति (एनईसी) के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर सीपीपी को 120 सीटें जीतीं तथा प्रिंस नोरोडोम चक्रवुध की फनसिनपेक पार्टी शेष पांच सीटें जीत सकी।

अल्जीरिया :जंगल की आग से मरने वालों की संख्या 34 हुई

अल्जीयर्स, (एजेंसी) अल्जीरिया के जंगल में आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, इसमें 10 सैनिक भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 11 प्रांतों में करीब आठ हजार लोग आग का सामना कर रहे हैं। आग से निपटने के लिए 529 ट्रकों और कई अग्निशमन हैलीकॉप्टरों का सहयोग लिया गया है। आग मुख्य रूप से बेजिया, जिजेल और बौइरा प्रांतों में रविवार रात भर लगी रही। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई जिससे काफी नुकसान हुआ। सोमवार देर रात तक 16 प्रांतों के जंगलों में आग लगने की 97 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे पहले दिन में 15 लोगों मौतें हुईं थी जो बढ़कर 34 हो गई।

मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी कांग्रेस विधायक के घर पर छापा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के परिसरों पर छापेमारी की। छोकर के बेटे सिकंदर सिंह गुरुग्राम में रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं और माहिरा ग्रुप नामक एक फर्म चलाते हैं, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। छोकर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि ईडी की टीमों ने छोकर की संपत्तियों और पेट्रोल पंपों के दस्तावेजों की जांच की और उनके अन्य व्यवसायों के बारे में भी पूछताछ की। ईडी की छापेमारी छोकर के जींद रोड स्थित आवास पर हुई।

बिन आंखों के जन्मे बच्चे का इलाज करवाएंगे सोनू

मुंबई,(एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बिन आंखों के जन्मे बच्चे का इलाज करवाएंगे। बिहार के नवादा में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी आंखें नहीं है। गरीबी के कारण परिवार अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पाया। किसी ने गुलशन नाम के इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो सोनू सूद तक पहुंच गया। इस वीडियो को देखने के बाद सोनू सूद ने गुलशन का इलाज करवाने का जिम्मा उठाया और ट्वीट करते हुए लिखा-'चल बेटा गुलशन, इलाज का समय हो गया। अब अपनी आंखों से दुनिया देख।' सोनू सूद गुलशन की आंखों का इलाज मुंबई में कराएंगे। सोनू सूद ने गुलशन के पिता राजेश चौहान और मां किरण

दिल्ली में गिरा बिल्डिंग का छज्जा, मां-बेटे की मौत

दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के पंजाबी बाद में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। जिसके मलबे में दबने से एक महिला और 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इमारत काफी पुरानी है। घटना दोपहर 1 बजे की है। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस समय हादसा हुआ। महिला का परिवार घर से अंदर सो रहा था। वहीं, हादसे के बाद मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने में जुट गए।

आज का इतिहास

- 1788: न्यूयॉर्क अमेरिका का 11वां राज्य बना।
- 1844: भारत के प्रमुख शिक्षाविद् गुरुदास बनर्जी का जन्म।
- 1876: कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना।
- 1945: विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया।
- 1951: नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त किया।
- 1953: कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति की शुरुआत।
- 1956: मिस्र का स्वेज नहर पर कब्जा।
- 1957: ग्वाटेमाला के तानाशाह कार्लोस कैस्टिलो अरमास की हत्या।
- 1965: मालदीव ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ।
- 1974: फ्रांस ने मुरुओरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया।
- 1997: श्रीलंका ने क्रिकेट एशिया कप जीता।

आईटीपीओ कांपलेक्स **2,254** करोड़ रु. लागत | **123** एकड़ क्षेत्र में बना | **7,000** लोग बैठ सकेंगे

सिडनी के ओपेरा हाउस से बड़ा होगा आईटीपीओ, मोदी करेंगे उद्घाटन

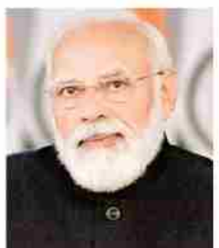

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रगति मैदान में नए सिरे से तैयार भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) कॉम्प्लेक्स सितंबर में भारत के नेतृत्व में जी-20 नेताओं की बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को होगा जो देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित जी-20 बैठकों का समापन होगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 26 जुलाई को इस पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन करेंगे हैं। प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के तहत आईईसीसी (एकीकृत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर) को एक आधुनिक परिसर के तौर पर तैयार किया गया है। परियोजना की कुल लागत 2,254 करोड़ रुपए है।

मंत्रालय ने बताया, लगभग 123 एकड़ क्षेत्र के साथ यह परिसर दुनिया के शीर्ष 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। सम्मेलन केंद्र के 'लेवल-3' पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से अधिक बड़ा बनाता है, जहां तकरीबन 5,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अधिकारियों के अनुसार, यह विशेषता आईईसीसी को वैश्विक पैमाने पर बड़े सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है।

27-28 को गुजरात दौरे पर पीएम राजकोट हवाईअड्डे का करेंगे उद्घाटन

राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राजकोट में नवनिर्मित हीरासर हवाईअड्डे का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए राज्य की राजधानी गांधीनगर में एक कार्यक्रम 'सेमीकॉन इंडिया 2023' का भी उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी प्रभाव जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को राजकोट शहर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने से पहले हीरासर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

फांगनोन कोन्याक रास कार्यवाही का संचालन करने वाली नगालैंड की पहली महिला सदस्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के संसदीय इतिहास में नगालैंड से पहली महिला सदस्य एस. फांगनोन कोन्याक ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही का सफलता पूर्वक संचालन किया और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 और जातियों को शामिल करने से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 पारित कराया।

श्रीमती कोन्याक ने 17 जुलाई को सदन के उप सभापति के पैनल में नियुक्त होने वाली नगालैंड से पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रचा था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले सप्ताह पैनल में कुल आठ सदस्यों के 50 प्रतिशत यानि चार महिला सदस्यों को उप सभापति पैनल में नामित किया था।

पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। श्रीमती कोन्याक भाजपा से हैं। वह अप्रैल, 2022 में नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं और संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के लिए चुनी जाने वाली राज्य की दूसरी महिला हैं। वह संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, सदन समिति तथा उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग की संचालन परिषद की सदस्य हैं। श्रीमती कोन्याक के अलावा श्रीमती पीटी उषा, डॉ. फौजिया खान और श्रीमती सुलता देव को भी उप सभापति पैनल में शामिल किया गया है।

मिली बधाईयां

डिप्टी सीएम और राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता वाई पैटन ने नई जिम्मेदारी संभालने पर फांगनोन को बधाई दी है। पैटन ने ट्वीट में लिखा कि उनका नामांकन उनके उल्लेखनीय समर्पण का प्रमाण है। बता दें कि मार्च 2022 में एस फांगनोन नगालैंड से राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला बनी थीं। इसके अलावा वह संसद के किसी भी सदन - लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली नगालैंड की दूसरी महिला राजनीतिज्ञ हैं। इससे पूर्व फांगनोन नगालैंड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थीं।

जैविक विविधता (संशोधन) बिल लोकसभा से पारित

नई दिल्ली (ब्यूरो)। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मंगलवार को जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने संक्षिप्त चर्चा के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। जैव विविधता अधिनियम 1992 में लाया गया था और पिछले लगभग 30 वर्षों में इससे जुड़ी विभिन्न समस्याएं सामने आई इसलिए जैव विविधता संरक्षण के लिए तथा समान बंटवारे के लिए यह संशोधन किये जाने जरूरी हो गये थे।

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन बिल लोस से पारित

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाया जिसने जैव विविधता से जुड़े उत्पादों के उपयोग पर काम किया और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा आकदमिक सहयोग बढ़ाने के लिए संशोधन आवश्यक लगे और इस लिहाज से यह संशोधन विधेयक लाया गया। श्री यादव ने कहा कि इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा संशोधन विधेयक लाया गया है। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी।

आयकर विभाग ने एक लाख करदाताओं को भेजा नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। आयकर विभाग ने देश के 1 लाख टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर की है। ये नोटिस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दी गई गलत जानकारी को लेकर भेजे गए। वित्त मंत्री ने 164वें आयकर दिवस समारोह के दौरान ये जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर विभाग ने 1 लाख लोगों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन टैक्सपेयर्स को भेजा गया, जिन्होंने या तो अपनी आय घोषित नहीं की है या फिर आय को कम बताया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई वजह

नींद के चलते होने वाले रोड एक्सीडेंट पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-बेस्ड एक ऐसे डिवाइस को विकसित किया है जो कि एक्सीडेंट रोकने में मदद करेगा। भारतीय सेना को इस डिवाइस को डेवलप करने के लिए पेटेंट सर्टिफिकेट भी मिल गया है। दरअसल, एआई-बेस्ड ये डिवाइस सड़क दुर्घटनाओं के पहले एक अलार्म बजाकर वाहन चालक को सचेत करेगा। खासतौर पर तब, जब वाहन चालक को नींद आ रही हो। सेना का कहना है कि इससे एक्सीडेंट पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल कुलदीप यादव ने इसे विकसित किया है। और इसके पेटेंट के लिए उन्होंने साल 2021 में ही आवेदन किया था, जिसे अब सर्टिफाई कर दिया गया है।

इंडियन आर्मी ने बनाया एआई-बेस्ड खास डिवाइस

मणिपुर में वायरल वीडियो मामले में कई गिरफ्तार

इंफाल, (एजेंसी)। इम्फाल के चुराचांदपुर जिले में पिछले तीन मई को दो जातीय समूहों के बीच शुरू हुई झड़पों के बाद हाल ही में राज्य में 80 वर्षीय महिला को जलाने, महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाने, यातना देने और युवकों को जिंदा जलाने समेत कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। इनमें कुछ वायरल वीडियो सही नहीं हैं जिसपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश हुए। कुछ शर्तों के साथ ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। मिजोरम में कुकी समर्थकों ने रैली निकाली।मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मुताबिक, युवा लड़कियों समेत स्कूली बच्चों के अपहरण और हत्या की भयावह कहानियां भी सामने आ रही हैं। विभिन्न लोगों द्वारा 6,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें एक बलात्कार का एक मामला भी शामिल था। मणिपुर हिंसा के खिलाफ मिजोरम के आईजोल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमेंमुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

83 दिनों बाद इंटरनेट कुछ शर्तों संग बहाल

महिला संग जवान ने छेड़खानी की, BSF ने सस्पेंड किया

मणिपुर हिंसा के बीच महिला से छेड़छाड़ का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक किराने की दुकान पर बीएसएफ जवान महिला के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। इंफाल का यह वीडियो 20 जुलाई का बताया जा रहा है। आरोपी हेड कॉन्स्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है। घटना सामने आने के बाद बीएसएफ ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दी पहने हुए जवान एक महिला को जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा है। जवान के पास राइफल भी है। वीडियो में महिला उसे बार-बार रोक रही है, फिर भी वो छेड़खानी कर रहा है।

पाकिस्तान पहुंची अंजू ने कुबूल किया इस्लाम फातिमा बनकर नसरुल्लाह से किया निकाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। फेसबुक फ्रेंड से मिलने हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू ने अब वहां धर्म परिवर्तन कर अंजू से फातिमा बन गई है। उसने धर्म परिवर्तन कर अपने दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। बता दें कि वीजा लेकर पाकिस्तान गई अंजू ने पहले कहा था कि वो बस अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने वहां गई और कुछ दिनों में लौट आएगी। हालांकि अब पाकिस्तान से उसके निकाह कर लेने की खबरें सामने आई है। अंजू भारत में पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। अंजू धर्म परिवर्तन करने से पहले ईसाई थी।

नसरुल्लाह ने निकाह से किया इनकार

हालांकि निकाह के बाद जब नसरुल्लाह से बातचीत की तो उसने शादी की बात से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं नसरुल्लाह ने ये भी कहा कि अंजू (फातिमा) उनकी दोस्त है और वो उससे प्यार नहीं करते हैं। हालांकि इस बीच दोनों का निकाहनामा सामने आया गया, जो नसरुल्लाह के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है।

कोझिकोड से मस्कट जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी

कोझिकोड, (आरएनएन)। केरल के कोझिकोड से मस्कट जा रही ओमान एयर की फ्लाइट को उड़ान के कुछ मिनट बाद ही लौटना पड़ा। लेकिन उसकी लैंडिंग तुरंत नहीं हो सकी। दरअसल, पायलट ने उतरने से पहले प्लेन का वजन कम करने के लिए ईंधन जलाया और 2 घंटे से ज्यादा समय तक कालीकट एयरपोर्ट का चक्कर लगाता रहा। एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, प्लाइट डब्ल्यूवाय 298 ने 169 लोगों के साथ सुबह 9.15 बजे एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनट में इसे वापस लैंड कराया गया।

दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग-ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को सदन में पेश करेगा।

अब संसद में पेश किया जाएगा

आप सदन में इस बिल का विरोध करेगी। उसे इस मामले में विपक्षी दलों का भी सपोर्ट हासिल है। दरअसल, केंद्र ने 19 मई को अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलटा, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।

केंद्र ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने 17 जुलाई को कहा कि हम यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि संविधान का आर्टिकल 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है।

डोभाल ने की वांग यी से मुलाकात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी में विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी से मुलाकात की और भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के परिणाम लाने पर जोर दिया। इस मुलाकात में श्री डोभाल ने कहा कि 2020 से भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर स्थिति ने रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को खत्म कर दिया है।

कुल्लू में बादल फटने से घरों को नुकसान, पुल बहे

शिमला, (आरएनएन)। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की गड़सा घाटी में मंगलवार सुबह बादल फटने से क्षेत्र के कुछ मकानों एवं कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा और इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दो पुल बह गए हैं और भुंतर-गड़सा सड़क कई स्थानों पर टूट गई है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि हुरला और कुरला पंचायत में पांच घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 15 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक, बादल फटने से इलाके में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है और कुछ सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। हिमाचल में 24 दिन में 27 बार बादल फटे, 158 की मौत हो गई।

'रॉकी और रानी...' के प्रीमियर में पत्नी आलिया भट्ट संग पहुंचे रणबीर कपूर, एक्स गर्लफ्रेंड से हुआ सामना

फिल्मी तड़का

मुंबई, (आरएनएन)। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ग्रैंड प्रीमियर पर आलिया भट्ट ब्लैक लूट टीशर्ट और लूज डेनिम पहने पति रणबीर कपूर के साथ दिखाई दीं। रणबीर ने इस दौरान ब्लैक फुल स्लीव्स टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। रणबीर आलिया इस दौरान साथ में काफी खूबसूरत लग रहे थे। रणबीर पत्नी आलिया संग इस फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे थे। तभी उनका सामना कुछ पुराने चेहरों से हो गया। जी हां, रणबीर कपूर जब आलिया के साथ प्रीमियर पर पहुंचे तो उनका सामना कैटरीना कैफ से हुआ। कैटरीना कैफ करण जौहर डायरेक्टेड फिल्म के प्रीमियर पर अपने पति विक्की कौशल के साथ पहुंची थीं। कैटरीना कैफ व्हाइट मिडी ड्रेस और ब्लैक लेदर बूट्स पहने दिखाई दीं। वहीं विक्की कौशल ब्लू डेनिम शर्ट और जींस में दिखाई दिए।

गंस एंड गुलाब्स' गंस एंड गुलाब्स'से गुलशन देवैया का लुक रिलीज

मुंबई, (आरएनएन)। बॉलीवुड अभिनेता गुलशन देवैया की आने वाली फिल्म 'गंस एंड गुलाब्स' से उनका लुक रिलीज हो गया है। गन्स एंड गुलाब्स एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित है। यह 90 के दशक के अपराध और हिंसा की दुनिया पर आधारित है।

इस फिल्म में राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव और टीजे भानु मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'गंस एंड गुलाब्स'से गुलशन देवैया का लुक रिलीज हो गया है। कहा जा रहा है कि गुलशन का गेटअप 90 के दशक के संजय दत्त के लुक से काफी प्रेरित है।

नोएडा में 500 वाहन डूबे

यमुना के बाद अब हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे यूपी के गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नोएडा के ईको-टेक इलाके में 500 वाहन डूब गए हैं। हिंडन नदी के खतरे का निशान 205.8 मिमी है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यह 201.5 मिमी है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

एकदिवसीय सीरीज देखने देर रात तक जागना होगा

मुम्बई टीम इंडिया के प्रशंसकों के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से शुरु हो रही तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज देखना कठिन रहेगा। इसका कारण मैच शुरू होने का समय है। एकदिवसीय सीरीज के मैच दोपहर 1-30 बजे शुरू होंगे। वहीं भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस प्रकार ये मैच रात करीब 3 बजे समाप्त होंगे। ऐसे में दर्शकों को मैच देखने के लिए देर रात तक जागना होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एकदिवसीय मैच टीवी पर डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले एकदिवसीय मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा एप पर भी देख सकते हैं।

भारत-वेस्टइंडीज पहला एकदिवसीय आज, युवा खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

शाम सात बजे से होगा मैच

ब्रिजटाउन।

भारतीय टीम गुरुवार को यहां मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में जीत से शुरुआत करने उतरेगी। टेस्ट सीरीज में मिली जीत से भारतीय टीम का मनोबल पहले ही बढ़ा हुआ है। आगामी एकदिवसीय विश्वकप को देखते हुए भी यह सीरीज अहम मानी जा रही है। इसलिए इसमें शामिल सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज में आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बेहतर प्रदर्शन कर इस प्रारूप में भी अपने को उपयोगी साबित करना चाहेंगे। वहीं विश्वकप में दूसरे विकेटकीपर के स्थान के लिये ईशान किशन और संजू सैमसन का नाम सबसे आगे हैं, ऐसे में ये दोनो भी इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे। भारत एशिया कप और विश्व कप के लिये टीम संयोजन तैयार करने के मकसद से इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों को आजामा रहा है। चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर भी इसके लिए यहां पहुंचे हैं। टेस्ट की तरह ही एकदिवसीय में भी भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है। इस सीरीज में सूर्यकुमार, ईशान, सैमसन, के अलावा युजवेंद्र चहल और उमरान मलिक के प्रदर्शन पर भी चयन समिति की नजरें रहेंगी। टी20 क्रिकेट में नंबर एक खिलाड़ी बने सूर्यकुमार चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह चौथे नंबर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे। सूर्यकुमार को पहले मैच में अंतिम ग्यारह में जगह मिलने की उम्मीद है। वहीं जांघ की सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन करा रहे लोकेश राहुल के नहीं होने के कारण उनकी जगह के लिए इस मैच में ईशान और सैमसन में से किसी एक को अवसर मिलेगा। सैमसन को टीम से भीतर बाहर होने की आदत है लेकिन 11 वनडे में 66 की औसत से रन बना चुके इस खिलाड़ी को टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ईशान को पहले मैच में विकेटकीपर की जिम्मेदारी मिलने की अधिक संभावना है। वहीं मध्यक्रम में सैमसन को जगह मिल सकती है। पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल करेंगे। ऐसे में युवा रूतुराज गायकवाड़ को शायद ही जगह मिले। वहीं तेज गेंदबाजी में गेंदबाज उमरान मलिक के पास इसी सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। उन्होंने सात वनडे में 13 विकेट लिए हैं। इस मैच में कुलदीप यादव की जगह पर यजुवेन्द्र चहल को शामिल किया जा सकता है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज के अलावा जयदेव उनादकट, मुकेश कमार और शार्दुल ठाकुर के पास रहेगी। वहीं दूसरी ओर मेजबान वेस्टइंडीज टीम इस बार एकदिवसीय विश्व कप के लिये क्वालीफाई नहीं कर सकी है और ऐसे में उसका लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन कर ये दिखाना होगा कि उसके पास अभी क्रिकेट प्रतिभाएं बरकरार हैं।

भारत-पाक मैच की तारीख बदलने को लेकर बीसीसीआई की राज्य क्रिकेट संघों के साथ बैठक आज

मुम्बई।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को सभी राज्य संघों की एक बैठक बुलायी है। इसमें एकदिवसीय विश्वकप में पाकिस्तान के खिलाफ 15 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले की तारीख बदलने पर चर्चा होगी। यह अहम बैठक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बुलायी है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार एकदिवसीय विश्व कप का यह महामुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना पर इसी दिन से नवरात्रि समारोह भी शुरु होने वाले हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बीसीसीआई से मैच का कार्यक्रम बदलने को कहा है। स्थानीय पुलिस ने बीसीसीआई से कहा है कि उस दिन सुरक्षा का ध्यान रखना कठिन होगा। मेजबानी के लिए तैयार राज्य संघों के साथ बीसीसीआई अधिकारियों की यह बैठक नई दिल्ली में होगी। इसमें यह तय है कि अहमदाबाद में होने वाले भारत-पाक विश्व कप मैच की तारीख में संभावित बदलाव पर फैसला होगा। अगर भारत-पाकिस्तान मैच पहले किया जाता है तो इसका असर एकदिवसीय विश्व कप के पूरे कार्यक्रम पर पड़ सकता है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, 14 अक्टूबर टूर्नामेंट में डबल हेडर वाला दिन है। विश्व कप मैच की तारीख में बदलाव से कई प्रशंसकों और अन्य प्रमुख हितधारकों पर भारी असर पड़ेगा, जिन्होंने पहले से ही इस मैच को लेकर अहमदाबाद के लिए आवास और उड़ान टिकट बुक कर लिए हैं।

पेरिस में 2024 ओलंपिक मशाल को लेकर नजर आये आयोजन समिति के प्रेसिडेंट टोनी एस्टेंग्युट और मेयर एनी हिडालगो।

बीसीसीआई ने घोषित किया कार्यक्रम, मोहाली में होंगे दो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले

मुम्बई।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अंतर्राष्ट्रीय घरेल सत्र 2023-24 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत टीम इंडिया 16 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी जिसमें 5 टेस्ट, 3 एकदिवसीय और 8 टी20 शामिल हैं। इसमें मोहाली में दो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले रखे गये हैं। इससे पहले पंजाब क्रिकेट संघ ने विश्वकप में मोहली को मेजबानी नहीं मिलने पर विरोध जताया था। इस मामले में पंजाब के खेल मंत्री मीत हेयर ने भी केन्द्र सरकार से भी शिकायत की अब जो कार्यक्रम आया है। उसमें एक एकदिवसीय और एक टी20 मुकाबला यहां रखा गया है।

इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत दौरे का पहला एकदिवसीय मैच 22 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। वहीं अफगानिस्तान टीम के भारत दौरे में 11 जनवरी को पहला टी-20 मोहाली में खेला जाएगा।

बीसीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय घरेल सत्र 2023-24 का कार्यक्रम इस प्रकार है -

- 22 सितंबर - पहला एकदिवसीय (मोहाली)
- 24 सितंबर - दूसरा एकदिवसीय (इंदौर)
- 27 सितंबर - तीसरा एकदिवसीय (राजकोट)

ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा (5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय)

- 23 नवंबर - पहला टी-20 इंटरनेशनल (वायजाग)
- 26 नवंबर - दूसरा टी-20 इंटरनेशनल (केरला)
- 28 नवंबर - तीसरा टी-20 इंटरनेशनल (गुवाहाटी)
- 01 दिसंबर - चौथा टी-20 इंटरनेशनल (नागपुर)
- 03 दिसंबर - 5वां टी-20 इंटरनेशनल (हैदराबाद)

अफगानिस्तान का भारत दौरा (3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय)

- 11 जनवरी - पहला टी-20 इंटरनेशनल (मोहाली)
- 14 जनवरी - दूसरा टी-20 इंटरनेशनल (इंदौर)
- 17 जनवरी - तीसरा टी-20 इंटरनेशनल (बेंगलुरु)

इंग्लैंड का भारत दौरा (5 टेस्ट)

- 25 से 29 जनवरी - पहला टेस्ट (हैदराबाद)
- 02 से 06 फरवरी - दूसरा टेस्ट (वायजाग)
- 15 से 19 फरवरी - तीसरा टेस्ट (राजकोट)
- 23 से 27 मार्च - चौथा टेस्ट (रांची)
- 07 से 11 मार्च - 5वां टेस्ट (धर्मशाला)

संक्षिप्त समाचार

स्पेन ने भारतीय हॉकी टीम को 2-1 से हराया हराया

बार्सिलोना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को यहां स्पेन हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित चार देशों के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान टीम ने 2-1 से हरा दिया। इस मुकाबले में स्पेन की ओर से पॉल क्यूनिल ने 11 वें मिनट जबकि जोक्विन मेनिनी ने 33 वें मिनट में गोल किये। वहीं भारतीय टीम की ओर से एकमात्र गोल हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट में दागा। भारतीय टीम ने शुरुआती क्वाटर्र में आक्रामक खेल दिखाया पर वह अपने प्रयासों को गोल में नहीं बढ़त पायी। मेजबान टीम के क्यूनिल ने पहले क्वाटर्र के समाप्त होने से पहले ही गोल दागर स्पेन को बढ़त दिला दी। वहीं भारतीय टीम ने दूसरे क्वाटर्र में वापसी के प्रयास किये पर वह सफल नहीं रही। भारतीय टीम ने तीसरे क्वाटर्र में कई हमले किये। इस दौरान स्पेन की ओर से मैनिनी ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। भारतीय टीम को तीसरे क्वाटर्र में एक पेनल्टी कॉर्नर मिला पर भारतीय टीम उसे गोल में नहीं बदल पायी। भारतीय टीम ने चौथे क्वाटर्र में बेहतर प्रदर्शन कर मेजबान टीम पर दबाव बनाया। इसी का लाभ उठाते हुए भारतीय टीम की ओर से 59वें मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में एक गोल दाग दिया। स्पेन ने इसके बाद कोई ओर गोले नहीं होने देते हुए मैच पर 2-1 से कब्जा कर लिया।

वॉर्नर और स्मिथ टेस्ट से ले सकते हैं संन्यास : वॉन

सिडनी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वान के अनुसार इस एशेज सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। एशेज का चौथा टेस्ट ड्रा के कारण यह सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। अब इंगलैंड का लक्ष्य किसी प्रकार अंतिम मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाना रहेगा। वॉन ने कहा कि बरसात के दिनों में ऐसा हमेशा होता है जब पत्रकार थोड़े ऊब जाते हैं और आप कुछ लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान स्मिथ और वार्नर के संन्यास की बातें सामने आयी है। वॉन बोले, स्मिथ के बारे में कहा जा रहा था कि ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच अंतिम होगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि हो सकता है कि मैनचेस्टर में बारिश के कारण ही लोग बात कर रहे हों पर कल प्रेस बॉक्स मे यही चर्चा थी कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खेल को अलविदा कह सकते हैं। वार्नर ने जनवरी 2024 से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की अपनी योजना का खुलासा किया था हाल के दिनों में उनका फार्म भी अच्छा नहीं है जिससे ये अफवाह और जोर पकड़ रही है। वहीं दूसरी ओर स्मिथ इस समय अच्छे फॉर्म में हैं। ऐसे में वॉन के अनुमान कितने सही है ये समय ही बताएगा।

आईसीसी महिला एकदिवसीय रैंकिंग में हरलीन, जेमिमा ऊपर आयीं

हरमनप्रीत को हुआ नुकसान

दुबई।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की महिला एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय टीम की हरलीन देयोल ओर जेमिमा रोड्रिग्स ने लंबी छलांग लगायी है। हरलीन को बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय में अर्धशतकीय पारी खेलने का लाभ मिला है। इसी के साथ ही हरलीन को रैंकिंग में 32 स्थान की बढ़त मिली है। इससे हरलीन ताजा आईसीसी रैंकिंग में 51वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं दूसरे एकदिवसीय में आक्रामक पारी खेलने वाली जेमिमा 41 स्थान के लाभ के साथ ही 55वें स्थान पर पहुंच गयी हैं। दूसरी ओर बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना के एक स्थान ऊपर आकर छठे स्थान जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर दो स्थान के नुकसान के साथ ही आठवें स्थान पर खिसक गयी हैं। गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो भारत की दीप्ति शर्मा 9 वें और राजेश्वरी गायकवाड़ 10 वे स्थान पर हैं। स्नेह राणा तीन पायदान ऊपर आगर 38वें स्थान पर हैं। दीप्ति ऑलराउंडरों की रैंकिंग में सावें स्थान पर हैं। वहीं इंग्लैंड की ऑलराउंडर नताली साइवर-ब्रंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला चैम्पियनशिप श्रृंखला के अंतिम एकदिवसीय मैच में शतक लगाने के साथ ही पहली बार आईसीसी महिला एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बनी हैं। इसी के साथ ही वह अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी से आगे निकल गईं हैं। उन्होंने ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर बनी वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज पर अपनी बढ़त 39 रेटिंग अंक तक बढ़ा ली है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर ऑलराउंडरों की सूची में दो पायदान ऊपर करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में भी करियर के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं।

विराट विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष-100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र भारतीय

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली रनों के साथ ही कमाई के मामले में भी अव्वल हैं। विराट विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष-100 खिलाड़ियों में शामिल हैं। इसमें केवल दो एशियाई खिलाड़ी शामिल हैं। विराट साल 2022 में सबसे अधिक रकम पाने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय हैं। उनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। वह साल 2022 के लिए जारी की गई शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान हासिल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61 वें स्थान पर हैं. भारतीय राष्ट्रीय टीम के अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले विराट ने वेतन और जीत से 2.9 मिलियन डॉलर और विज्ञापन से 31 मिलियन डॉलर कमाए हैं। उनकी कुल कमाई 33.9 मिलियन डॉलर आंकी गई है हालांकि वह 2021 में अपनी 59वीं रैंक से दो स्थान नीचे गिर गए हैं। कोहली के अलावा, इस सूची में एशिया से एकमात्र अन्य खिलाड़ी जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका हैं। 25 वर्षीय साल की ओसाका ने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम, दो अमेरिकी ओपन और दो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीते हैं। ओसाका इस सूची में 20वें स्थान पर आने वाली शीर्ष एशियाई खिलाड़ी हैं। ओसाका की कुल कमाई 53.2 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जिसमें केवल 1.2 मिलियन डॉलर जीत से और 52 मिलियन डॉलर विज्ञापन से प्राप्त हुए हैं।

जय शाह ने ऋषभ, बुमराह और श्रेयस की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अभी बेंगलुरु की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अपनी फिटनेस हासिल कर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की है। ये सभी खिलाड़ी यहां रिहैब के दौर से गुजर रहे हैं। अभी इनके फिटनेस और कौशल पर काम जारी है। बुमराह और कृष्णा दोनों तेज गेंदबाज अपने पुनर्वास के अंतिम चरण में हैं और नेट्स में पूरी तेज के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। यह जोड़ी अब कुछ अभ्यास मैच खेलेगी, जिसका आयोजन एनसीए करेगा। बीसीसीआई मेडिकल टीम उनकी प्रगति से खुश है और अभ्यास खेलों की समीक्षा के बाद उनपर अंतिम फैसला करेगी। राहुल और अय्यर ने नेट्स पर बल्लेबाजी फिर से शुरू कर दी है और वर्तमान में ताकत और फिटनेस अभ्यास से गुजर रहे हैं। बीसीसीआई मेडिकल टीम उनकी प्रगति से संतुष्ट है और आने वाले दिनों में कौशल, ताकत और कंडीशनिंग दोनों के मामले में अपनी तीव्रता बढ़ाएगी। वहीं ऋषभ अपनी फिटनेस हासिल करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह नेट्स पर बल्लेबाजी कर रहा है। साथ ही साथ विकेटकीपिंग का भी अभ्यास कर रहे हैं।

फीफा महिला विश्व कप - फिलीपींस ने न्यूजीलैंड को हराकर सबको किया हैरान

कोलंबिया ने दक्षिण कोरिया को हराया

सिडनी।

फिलीपींस ने फीफा महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड को 1-0 से हराकर इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई मुकाबला जीता है। वहीं एक अन्य मुकाबले में कोलंबिया ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हरा दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप ए में नॉर्वे ने स्विट्जरलैंड के साथ हुए मुकाबले में गोल रहित ड्रॉ खेला। इस मैच में नॉर्वे को अपने स्टार फ़ॉरवर्ड एडा हेगरबर्ग के बिना ही खेलना पड़ा। अब नॉर्वे को दो गेम में केवल एक अंक ही मिला है। अब उसे फिलीपींस से होने वाले अपने अंतिम ग्रुप मैच को किसी भी हालत में जीतना होगा। फिलीपींस ने ग्रुप के एक अन्य मैच में न्यूज़ीलैंड को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था। सरीना बोल्डन ने 24वें मिनट में फिलीपींस की ओर से विजयी गोल कर खेलों के सह मेजबान को हैरान कर दिया था। फिलीपींस के कोच एलन स्टैजिक ने कहा, मेरी आंखों में बाकी सभी के आंसू हैं, यह बहुत भावुक करने वाला है। आपने देखा कि न्यूजीलैंड को अपनी पहली जीत के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। इसलिए फिलीपींस के लिए आज उसे हासिल करना अविश्वसनीय था। वहीं अपने पहले मैच में नॉर्वे पर ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूज़ीलैंड टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर उतरी थी। न्यूजीलैंड ने दूसरे हाफ में बराबरी हासिल करने के लिए कई अच्छे आक्रमक किये पर उसके खिलाड़ी उन्हें गोल में बदल नहीं पाये। हार के बाद निराश न्यूजीलैंड के कोच जित्का क्लिमकोवा ने कहा, यह दिल तोड़ने वाला था, मैं अपने खिलाड़ियों की आंखों में आंसू देख सकता था। पर यह अभी सबकुछ समाप्त नहीं हुआ है। हमें अभी भी एक गेम खेलना बाकी है। स्विट्जरलैंड के खिलाफ गेम से पहले हमारे पास अभी भी अपना ध्यान केन्द्रित करने समय है। वहीं एक अन्य मैच में किशोरी लिंडा कैसिडो के गोल से कोलंबिया ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हरा दिया। 18 वर्षीय कैसिडो ने पहले हाफ के अंत में कोलंबिया के लिए दूसरा गोल दागा। वहीं दक्षिण कोरियाई टीम पहले हाफ के अधिकांश समय पीछे रही और कोलंबिया की मजबूत रक्षापंक्ति का सामना करने में विफल रही। दक्षिण कोरिया ने 78वें मिनट में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 16 वर्षीय फॉरवर्ड केसी फेयर को उतारा पर वह भी कोई कमाल नहीं कर पायी।

भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश रोहित बोले, वेस्टइंडीज में खेलना अलग प्रकार की चुनौती

पोर्ट ऑफ स्पेन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि वेस्टइंडीज में खेलना अपने आप में एक अलग प्रकार की चुनौती है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली है और अब उसे तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलनी है। रोहित ने कहा कि वेस्टइंडीज में खेलने की अपनी चुनौती है और जिस तरह से चीजें उनकी टीम के लिए रहीं, उससे वह संतुष्ट हैं। भारतीय टीम यहां बारिश के कारण दूसरा टेस्ट मैच नहीं जीत पायी थी। रोहित ने मैच के बाद कहा, हर जीत अलग होती है। वेस्टइंडीज में खेलने की अपनी चुनौती होती है। जिस तरह से चीजें हुईं, उससे खुश हूं। हमने अच्छा प्रयास किया, बदकिस्मती से अंतिम दिन बारिश होने के कारण हमारे हाथ से जीत निकल गयी। हम सकारात्मक इरादे के साथ उतरे थे। बारिश ने अंतिम फैसला किया। हम काफी आश्वस्त थे। आप जानते हैं कि अंत में बल्लेबाजी करना वेस्टइंडीज के लिए कितना मुश्किल रहेगा। हम हमेशा उस तरह का स्कोर चाहते थे, जहां हम चाहते थे कि विपक्षी टीम इसके लिए आगे बढ़े। सतह पर ज्यादा कुछ नहीं था। अंतिम दिन खेल नहीं होने से हमारे हाथ से जीत का अवसर निकल गया। उन्होंने कहा कि वह एक टीम के रूप में बेहतर होने में विश्वास करते हैं।रोहित ने कहा, मैं हमेशा एक टीम के रूप में बेहतर होने में विश्वास करता हूं। मैंने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद भी कहा था। हमने लगातार क्रिकेट खेला है। हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं। हम खेल के सभी तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। रोहित ने दूसरे टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और युव बल्लेबाज ईशान किशन की प्रशंसा की।

मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया गया, मेरा अपमान हुआ है : खड़गे

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। राज्य सभा में बुधवार को भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि सदन के अंदर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया गया है। खड़गे ने कहा कि कम से कम जब मैं बोल रहा हूं तो अचानक मेरा माइक बंद करना, यह मेरा अपमान है। यह मेरा प्रिविलेज है, मेरे प्रिविलेज को धक्का लगा है, मेरा अपमान हुआ है।

दरअसल, विपक्ष के सांसदों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। लेकिन, अचानक उनका माइक बंद कर दिया गया। खड़गे का कहना है कि उन्हें सदन में अपनी बात नहीं रखने दी गई। मंगलवार को इसके बाद नाराज विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए बॉयकॉट का फैसला किया था।

मणिपुर में हुई हिंसा पर चर्चा का मुद्दा संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का विषय बन रहा है। विपक्ष की अधिकांश पार्टियां इस मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत विस्तार से चर्चा चाहती है। जबकि, सरकार व सभापति इस विषय पर शार्ट डिस्कशन के लिए अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। इसी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को भी राज्यसभा में यह टकराव देखने को मिला। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अपने अपमान का मुद्दा उठाया।

खड़गे ने मंगलवार को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैं ये सोचकर उठा था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। खड़गे ने कहा कि मैं अपने मुद्दे सदन के सामने रख रहा था, 50 लोगों ने 267 पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। खड़गे ने कहा, कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना, ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरे प्रिविलेज को धक्का है, मेरा अपमान हुआ है। आपने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को चैलेंज किया।

खड़गे ने यह भी कहा कि अगर सरकार के इशारे पर सदन चलेगा तो मैं समझूंगा कि यह लोकतंत्र नहीं है। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों द्वारा हंगामा शुरू हो गया जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

हालांकि, इसी दौरान राज्यसभा में कुछ हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले। खड़गे जब बोल रहे थे तो उनके पीछे की सीटों पर कई कांग्रेस सांसद खड़े हो गए। इस पर सभापति ने कहा, आपके पीछे आपके सांसद खड़े हैं। सभापति की टिप्पणी पर खड़गे ने कहा कि हमारे सांसद हमारे पीछे नहीं तो क्या पीएम मोदी के पीछे खड़े होंगे। इसके बाद सभापति के साथ-साथ अन्य सांसदों ने भी ठहाके लगाए। इस बीच सत्ता पक्ष के सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए।

राजनाथ सिंह ने द्रास में करगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बुधवार को लद्दाख के द्रास शहर में कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

1999 से हर साल आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर के टाइगर हिल और अन्य रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया गया था।

पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि उसके नियमित सैनिक आक्रमण में शामिल थे और इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने भारतीय सेना के साथ कार्रवाई में मारे गए अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया।

रक्षा मंत्री कारगिल विजय दिवस के महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए द्रास पहुंचे। सम्मान और सम्मान के संकेत के रूप में, उन्होंने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन साहसी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी युद्ध नायकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने भी इस महत्वपूर्ण दिन पर कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की।

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की अदम्य भावना और बलिदान को स्वीकार करते हुए स्मारक पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता का सम्मान करने का समय है, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 'ऑपरेशन विजय' को विजयी निष्कर्ष तक पहुंचाया। यह दिन उन सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अटूट समर्पण और साहस की मार्मिक याद दिलाता है जिन्होंने संघर्ष के दौरान देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की।

रक्षा मंत्री ने शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और सम्मान स्वरूप प्रत्येक परिवार को एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल भेंट की।

देश के रक्षा बलों के संकल्प और ऊंचे मनोबल को सलाम करते हुए, राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, 'हम जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई भी भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता।

'सिर्फ कारगिल ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद से आज तक कई बार आपकी वीरता ने समय-समय पर देश को गौरवान्वित किया है।'

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, 'कारगिल विजय दिवस पर, मैं उन बहादुर सैनिकों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने शानदार वीरता प्रदर्शित की और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं विनम्रतापूर्वक हमारे कारगिल युद्ध नायकों के परिवारों को नमन करता हूं।' राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान और सेवा के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

द्रास शहर में कारगिल युद्ध स्मारक पर शौरा संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां वीर भूमि पर बहादुरों के प्रतीक 559 दीपक जलाए गए।

सेना ने अपने ट्विटर पेज पर कहा, 'कारगिल विजय दिवस उन बहादुरों की निडर बहादुरी और साहस की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने खून और बलिदान से इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखा। उन्होंने दुश्मन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया और इस राष्ट्र की शानदार जीत हुई।'

भारत के बहादुरों के बलिदान को याद करने के लिए मंगलवार को एक मोटरसाइकिल रैली ड्रैसन पहुंची।

रैली द्वारा दिए गए संदेश पर प्रकाश डालते हुए सेना की उत्तरी कमान ने कहा, '24वें कारगिलविजयदिवस की पूर्व संध्या पर,नारी सशक्तीकरण महिला मोटरसाइकिल रैली के 25 फौलादी सवारों ने जोखिम भरे इलाके और मौसम में सभी बाधाओं का सामना किया और अपनी 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की।' कारगिल, वास्तव में 24 साल पहले कारगिलयुद्ध में हमारे वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी, दृढ़ संकल्प और असाधारण बलिदानों का प्रतीक है और इसे फिर से जीवंत करता है। रैली को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना कमांडर एनसी ने हरी झंडी दिखाई, जिन्होंने उनकी बहादुरी, उद्देश्य की भावना को सलाम किया और राष्ट्रनिर्माण में योगदान।'

विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के विरोध के बीच निचले सदन ने बुधवार को वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिया। विपक्ष मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और लोकसभा में उनकी मौजूदगी की मांग कर रहा है। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

विधेयक का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम (1980) में संशोधन करना है, जिसे भारत के वन भंडार के शोषण को रोकने के लिए लाया गया था और केंद्र सरकार को गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की शक्ति दी गई थी। प्रस्तावित कानून कुछ प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।

राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है। विधेयक इसे सभी संस्थाओं तक विस्तारित करता है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है। इस पर चर्चा में केवल चार सांसदों के भाग लेने के बाद विधेयक को 40 मिनट के भीतर ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे कृषि-वानिकी, जैव विविधता और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह विधेयक पहली बार इस साल 29 मार्च को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि, कई विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बीच इसे जांच के लिए भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व वाली संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। विधेयक के सभी प्रावधानों को स्वीकार करते हुए समिति की रिपोर्ट 20 जुलाई को संसद में रखी गई थी।

ठीक हो चुके 2,000 से ज्यादा लोग अब भी मानसिक अस्पतालों में, यह न्याया का मजाक : एनएचआरसी प्रमुख

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि ठीक हो चुके 2,000 से अधिक मरीजों को अब भी देश के मानसिक अस्पतालों में रखा गया है, जबकि उन्हें एक दिन भी वहां नहीं रहना चाहिए। एनएचआरसी प्रमुख ने यहां विज्ञान भवन में मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, 'अस्पताल ऐसी जगह नहीं है जहां ठीक हो चुके मरीजों को एक दिन भी अतिरिक्त रहने की अनुमति दी जाए।' अपने संबोधन में उन्होंने एनएचआरसी द्वारा तैयार एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जो जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक देश के विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के आयोग और उसके विशेष प्रतिवेदकों की टीमों द्वारा किए गए दौरों पर आधारित है।

रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में 2,000 से अधिक ठीक हो चुके मरीज हैं, जबकि अस्पताल में एक भी ठीक मरीज नहीं होना चाहिए। एक अस्पताल एक ठीक हो चुके रोगी के लिए एक जगह नहीं है। लेकिन, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनमें से आधे (900 से अधिक रोगियों) को पश्चिम बंगाल के चार अस्पतालों में रखा गया है। यह न्याय का उपहास है।'

हाल के दिनों में आयोग ने ग्वालियर, आगरा और रांची में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों का दौरा किया। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों में स्थितियों के निष्कर्षों ने आयोग को विभिन्न राज्यों में सभी 47 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करने के लिए अपने विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके निष्कर्षों के परिणामस्वरूप देश में 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति' और संबंधित चुनौतियों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार हुई। यह रिपोर्ट सम्मेलन के दौरान जारी की गई।

एनएचआरसी प्रमुख ने यह भी रेखांकित किया कि समाज को 'मानसिक स्वास्थ्य कलंक को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समझ और करुणा को बढ़ावा देता है'। उन्होंने कहा, 'हमें मानसिक बीमारी के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता है। मानसिक बीमार स्वास्थ्य स्थितियों में गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के माध्यम से गरिमा प्राप्त करना है, जिसने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक प्रतिमान बदलाव लाया और इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना और आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है।

एनआईए ने बंगाल पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

कोलकाता, 26 जुलाई (एजेन्सी)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन पर इस साल रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा की चल रही जांच में असहयोग का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए ने राज्य प्रशासन पर मामले से संबंधित दस्तावेज उन्हें सौंपने की प्रक्रिया में देरी करने का आरोप लगाया है। यह पहली बार नहीं है जब एनआईए ने राज्य प्रशासन पर मामले में असहयोग का आरोप लगाया है। इससे पहले 19 जून को एनआईए ने इसी शिकायत के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ का रुख किया था।

हाल ही में, न्यायमूर्ति मंथा को डिवीजन-बेंच न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसलिए केंद्रीय एजेंसी ने अब इस मामले में न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ का दरवाजा खटखटाया है। पीठ ने इस संबंध में एनआईए की याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

मामले की एनआईए जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने दिए थे। हालांकि, राज्य सरकार ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी कि एनआईए जांच का आदेश जनहित याचिका के आधार पर दिया गया था, जो राज्य सरकार के अनुसार अनुचित था।

इस मुद्दे पर राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों - मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा - की पीठ ने खारिज कर दिया था।

इस साल 27 अप्रैल को मामले की एनआईए जांच का आदेश देते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि उन लोगों को ढूंढना राज्य पुलिस की क्षमता से परे है जो झड़प के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने हिंसा के लिए उकसाया था और इसलिए एनआईए द्वारा जांच जरूरी थी।

हमारे तीसरे कार्यकाल में शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचकर रहेगा भारत : पीएम मोदी

राजेश अलख

नई दिल्ली, 26 जुलाई । पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स 'भारत मंडपम' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पहले कार्यकाल में भारत दुनिया की दसवें नंबर की अर्थव्यवस्था था, अब दूसरे कार्यकाल में हम पांचवे नंबर पर आ गए हैं और हमारे तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। आगे बोले कि ये मोदी की गारंटी है। आप 2024 के बाद अपने सपनों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे।

उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल में आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे कार्यकाल में दुनिया की पहली तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक नाम भारत का होगा। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है।

प्रगति मैदान में आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बातें कहीं तो पूरा सभागृह मोदी-मोदी के उद्घोष से गूंज उठा। इस आत्मविश्वास से भरी गर्जना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे आंकड़ों के माध्यम से 2014 के पहले और उसके बाद देश में हुए विकास कार्यों की तुलना की। इन आंकड़ों के माध्यम से मोदी ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर करारा तंज किया।

पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि आज सपनों को साकार होते हुए देख रहा हूं। सबसे पहले पीएम ने एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने है। भव्य है, विराट है। आज अपनी आंखों के सामने सपनों को साकार होते हुए देख रहे हैं तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है। भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई उर्जा का आह्वान है। भारत मंडपम भारत की भव्यता और इच्छाशक्ति का दर्शन है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह करगिल विजय दिवस है। हमारे वीर बेटे-बेटियों ने देश के दुश्मनों को हराया। मैं करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले हर नायक को श्रद्धांजलि देता हूं।कॉम्ख्रलेक्स के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मंडपम देखने के बाद हर भारतीय खुश है, गर्व से भरा है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस कॉम्ख्रलेक्स के निर्माण को रोकने के लिए नकारात्मक सोच वालों ने क्या-क्या कोशिशें नहीं की, अदालतों के चक्कर काटे थे। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने, टोकने की। जब कर्तव्य पथ पर बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थीं। अखबार, ब्रेकिंग न्यूज में न जाने क्या-क्या चल रहा था। कर्तव्य पथ बनने के बाद वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे कि अच्छा हुआ है।

बता दें कि प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के तहत आईईसीसी (एकीकृत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर) को एक आधुनिक परिसर के तौर पर तैयार किया गया है। परियोजना की कुल लागत 2,254 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने बताया, लगभग 123 एकड़ क्षेत्र के साथ यह परिसर दुनिया के शीर्ष 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। सम्मेलन केंद्र के लेवल-3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से अधिक बड़ा बनाता है, जहां तकरीबन 5,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।

भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी, किरेन रिजिजू ने किया दावा

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेन्सी)। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां दुनिया भर की सभी प्रणालियों से बेहतर हैं। मौसम विभाग की मौसम को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणी की सटीकता में भी सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इसके परिणाम सटीक रहे हैं।

रिजिजू ने पत्रकारों से कहा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और उसके परिणाम दुनिया भर में अन्य सभी प्रणालियों की तुलना में काफी बेहतर हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वानुमान में सुधार के साथ ही आपदा से संबंधित मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि डॉपलर रडार की संख्या 2013 में 15 थी, जोकि अब बढ़कर 35 हो गई है। इसके अलावा भारत अगले तीन वर्षों में और रडार जोड़ेगा। इसके बाद यह संख्या 68 हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि साल 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

आईएमडी को लेकर रिजिजू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर मौसम एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन आईएमडी की चेतावनियों का पालन करके उन्हें कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने 2014 के बाद से जबरदस्त काम किया है। इस साल चक्रवात बिपरजॉय को लेकर सही जानकारी दी।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com